नई दिल्ली ■ बुधवार 11 मार्च 2026 ■ मूल्य 5.00 ■ वर्ष 13 ■ अंक 342 ■ पृष्ठ 08

JBT जनभावना टाइम्स

www.thejbt.com

निष्पक्ष और निर्भीक खबर

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, गौतमबुद्ध नगर, देहरादून, लखनऊ, अलीगढ़, मथुरा, हिसार, कैथल एवं करनाल से प्रकाशित

04 निकोटीन का जहर और समाज का मौन संकट | 07 मैथ्यू हेडन को गुजरात टाइटन्स ने बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया | सोहा अली खान का 'फुल सर्कल मोमेंट'... 08

कैबिनेट ने दी रेलवे की दो मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी

पश्चिम बंगाल व झारखंड में 192 किमी नेटवर्क का होगा विस्तार

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने मंगलवार को रेल मंत्रालय की दो मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। इनकी कुल अनुमानित लागत 4,474 करोड़ रुपये है और इन्हें वर्ष 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहां राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में संवाददाता सम्मेलन में मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्वीकृत परियोजनाओं में सैंथिया–पाकुड़ चौथी लाइन (81 किमी) तथा संतरागाछी–खड़गपुर चौथी लाइन (111 किमी) शामिल हैं। इन परियोजनाओं से भारतीय रेलवे की मौजूदा नेटवर्क क्षमता में लगभग 192 किलोमीटर की वृद्धि होगी। उन्होंने संतरागाछी-खड़गपुर चौथी लाइन परियोजना को लेकर कहा कि संतरागाछी कोलकाता के चार बड़े रेलवे स्टेशनों में से एक है। इस स्टेशन पर बहुत सारा विकास कार्य चल रहा है। यह छह मंजिला स्टेशन बनकर तैयार हो रहा है। सरकार के अनुसार इन परियोजनाओं से रेलवे की लाइन क्षमता बढ़ेगी, जिससे परिचालन दक्षता और सेवा की विश्वसनीयता में सुधार होगा। मल्टीट्रैकिंग के माध्यम से ट्रेनों की आवाजाही अधिक सुगम होगी और रेलवे मार्गों पर भीड़भाड़ कम करने में मदद मिलेगी। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत तैयार की गई हैं, जिनका उद्देश्य मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स दक्षता को बढ़ाना है। इसके माध्यम से लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही अधिक सुगम होगी। दोनों परियोजनाएं पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुल पांच जिलों को कवर करेंगी। इससे लगभग 5,652 गांवों को बेहतर रेल संपर्क मिलेगा, जहां करीब 1.47 करोड़ की आबादी निवास करती है।

इन परियोजनाओं से बोलपुर-शांतिनिकेतन, नंदिकेश्वरी मंदिर (शक्तिपीठ), तारापीठ (शक्तिपीठ), पटचित्र ग्राम, धादिका वन, भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य और रामेश्वर कुंड जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों की रेल कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। सरकार के अनुसार यह मार्ग कोयला, पत्थर, डोलोमाइट, सीमेंट, स्लैग, जिप्सम, लोहा-इस्पात, खाद्यान्न, पेट्रोलियम उत्पाद और कंटेनर जैसे सामानों के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण हैं। क्षमता विस्तार के बाद करीब 31 मिलियन टन प्रति वर्ष अतिरिक्त माल परिवहन संभव होगा। परियोजनाओं के पूरा होने से लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी, तेल आयात में लगभग 6 करोड़ लीटर की कमी आएगी तथा करीब 28 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी होगी, जो लगभग एक करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।

जल जीवन मिशन को मिला विस्तार, सभी 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों को मिलेगा नल कनेक्शन

नई दिल्ली। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) की अवधि को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। जेजेएम 2.0 के तहत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अतिरिक्त आवंटन और पुनर्गठित कार्यान्वयन शामिल है। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत दिसंबर 2028 तक देशभर के सभी 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल के पानी का कनेक्शन प्रदान किया जाएगा।

ऐतिहासिक बासक्यूल पुल के नवीनीकरण को मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कोलकाता पोर्ट स्थित ऐतिहासिक बासक्यूल पुल के नवीनीकरण को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर 117.54 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता के डॉक सिस्टम की सुरक्षा और परिचालन क्षमता को बढ़ावा मिलेगा।

जेवर एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी निर्माण की पूंजी लागत में संशोधन

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी के निर्माण की कुल पूंजी लागत में संशोधन किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने बैठक में उक्त आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

मदुरै एयरपोर्ट होगा अंतरराष्ट्रीय

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने मंगलवार को तमिलनाडु के मुदरै एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय दर्जा दिए जाने की घोषणा की। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज उक्त आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।

उज्जैन को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 4-लेन कॉरिडोर को मंजूरी

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने उज्जैन को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले 3,839 करोड़ रुपये के 4-लेन कॉरिडोर को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज बैठक में उक्त आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

ईरान ने इजराइल, खाड़ी देशों पर नए हमले किए

दुबई। ईरान ने मंगलवार को दबाव बनाने की नीति के तहत इजराइल और खाड़ी देशों पर नए हमले किए। इस युद्ध के चलते तेल की कीमतों में उछाल लाया है और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में मिसाइलों की चेतावनी वाले सायरन बजने लगे, जबकि बहरीन में अधिकारियों ने कहा कि ईरान ने राजधानी में एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया जिसमें 29 वर्षीय एक महिला मारी गई जबकि आठ अन्य घायल हो गए।

इस बीच, सऊदी अरब ने कहा कि उसने अपने तेल समृद्ध पूर्वी क्षेत्र में दो ड्रोन को नष्ट कर दिया, जबकि कुवैत के नेशनल गार्ड ने कहा कि उसने छह ड्रोन मार गिराए हैं। बाद में सुबह के समय, यरूशलम में भी सायरन बजने लगे और तेल अवीव में विस्फोटों की आवाजें सुनाई दीं। इस बीच, ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर क़लीबाफ़ ने 'एक्स' पर चुनौती भरे लहजे में लिखा कि हम निश्चित रूप से अभी संघर्षविराम के पक्ष में नहीं हैं। हमारा मानना है कि हमलावर के मुंह पर मुक्का मारा जाना चाहिए ताकि उसे सबक मिले और वह फिर कभी हमारे प्यारे ईरान पर हमला करने के बारे में न सोचे।

वहीं, ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे धमकी दी। उन्होंने लिखा कि ईरान जैसा बलिदानी राष्ट्र तुम्हारी खोखली धमकियों से नहीं डरता। तुमसे बड़े भी ईरान को खत्म नहीं कर सके। सावधान रहें, कहीं खुद आपका सफाया न हो जाए। अतीत में ईरान पर ट्रंप की हत्या की साजिश रचने का आरोप लग चुका है। खाड़ी क्षेत्र में इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलों तथा ड्रोन से हमला करने के अलावा ईरान ऊर्जा अवसंरचना को भी निशाना बना रहा है और होर्मुज जलडमरूमध्य पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है जिससे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार 'ब्रेंट क्रूड' की कीमत सोमवार को बढ़कर लगभग 120 डॉलर तक पहुंच गई।

राजौरी में एक पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर

राजौरी। सेना के जवानों ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास घुसपैठ की कोशिश करते एक आतंकवादी को मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। व्हाइट नाइट कोर ने बताया कि खुफिया सूचनाओं पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने दोपहर करीब तीन बजे एलओसी के पास नौशेरा सेक्टर के झंगड़ के सामान्य इलाके में दो आतंकवादियों की गतिविधियों का पता लगाया। गोलीबारी होने पर एक पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया गया।

भारत में घरेलू उपभोक्ताओं को ईंधन की कोई कमी नहीं होगी : हरदीप सिंह पुरी

नई दिल्ली। केंद्रीय पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को भरोसा दिलाया कि भारत में घरेलू उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम पदार्थों (पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और पीएनजी) की कोई कमी नहीं होगी।

उन्होंने आश्वासन दिया कि देश में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। केंद्रीय पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री ने 'एक्स' पोस्ट पर जारी एक बयान में ये भरोसा दिलाया कि भारत में घरेलू उपभोक्ताओं को ईंधन की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि देश में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और वैश्विक तनाव के बावजूद निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। हरदीप सिंह पुरी ने भरोसा दिलाया कि भारत में घरेलू कंज्यूमर्स के लिए एनर्जी की कोई कमी नहीं है और घबराने की कोई बात नहीं है।

पेट्रोलियम मंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत का ऊर्जा आयात अलग-अलग सोर्स और रास्तों से लगातार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने यह पक्का करने के लिए कई कदम उठाए हैं कि घरेलू उपभोक्ताओं को सीएनजी और पीएनजी की 100 फीसदी सप्लाई हो, और पश्चिम एशिया के मौजदा हालात के बावजूद दूसरी इंडस्ट्रीज को उनकी सप्लाई का 70 से 80 फीसदी मिलता रहे।

भारत ने मोजाम्बिक में बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजी राहत सामग्री

नई दिल्ली। पूर्वी अफ्रीकी देश मोजाम्बिक के मध्य और दक्षिणी प्रांतों में आई बाढ़ से मची तबाही के बीच भारत ने मंगलवार को व्यापक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू किया है।

विदेश मंत्रालय के अनुसार संकट की इस घड़ी में मोजाम्बिक के साथ भारत ने एकजुटता दिखाते हुए यहां के लिए खाद्य सुरक्षा और चिकित्सा सुविधाओं सहित अन्य बहुआयामी सहायता प्रदान की है।

इसमें तत्काल खाद्य सहायता के रूप में 500 मीट्रिक टन चावल और 10 मीट्रिक टन अन्य राहत सामग्री भारतीय नौसेना के जहाज के जरिए भेजी गई है।

जिष्णु देव वर्मा ने महाराष्ट्र के राज्यपाल पद की शपथ ली

मुंबई। महाराष्ट्र के नवनियुक्त राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने मंगलवार को लोकभवन में राज्यपाल पद की शपथ ली। मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति चंद्रशेखर ने लोकभवन के दरबार हॉल में आयोजित शपथग्रहण समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

बंगाल में जमीनी स्तर पर कानून-व्यवस्था की तैयारी के आधार पर तय होंगे चुनाव के चरण: ज्ञानेश कुमार

कोलकाता। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मंगलवार को कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव कितने चरणों में कराए जाएंगे, इसका अंतिम निर्णय राज्य में जमीनी स्तर पर कानून-व्यवस्था की स्थिति और प्रशासनिक तैयारियों को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आयोग की पूर्ण पीठ ने पिछले दो दिनों के दौरान राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की है।

इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस और अन्य संबंधित पक्षों के साथ बैठकें कर चुनावी तैयारियों का जायजा लिया गया। सभी पक्षों ने आयोग को आश्वासन दिया है कि मतदान शांतिपूर्ण, निर्भीक और हिंसामुक्त वातावरण में कराया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव कितने चरणों में होंगे, यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था की स्थिति कैसी है और मतदान को सुरक्षित तरीके से कराने के लिए क्या व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं।

आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक मतदाता बिना किसी भय के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। उन्होंने यह भी बताया कि समीक्षा यात्रा के दौरान आयोग की पूर्ण पीठ ने राज्य प्रशासन के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे कानून के शासन को सख्ती से लागू करें और किसी भी प्रकार के दबाव, भय या पक्षपात से मुक्त होकर काम करें। अधिकारियों का निष्पक्ष और पारदर्शी आचरण चुनाव की विश्वसनीयता के लिए अत्यंत आवश्यक है। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव से पहले, मतदान के दौरान और मतदान के बाद होने वाली किसी भी प्रकार की चुनावी हिंसा के प्रति आयोग की नीति शून्य सहनशीलता की है।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी व्यक्ति चुनावी हिंसा में शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के कारण मतदाताओं को हो रही कथित असुविधा के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह एक राष्ट्रीय स्तर की प्रक्रिया है, जिसे निर्धारित अंतराल पर सभी राज्यों में लागू किया जाता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष ढंग से और विभिन्न स्तरों के अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी के साथ पूरी की गई है। उन्होंने बताया कि तार्किक विसंगति की श्रेणी में चिन्हित मतदाताओं से जुड़े मामलों की न्यायिक सुनवाई उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप और कलकत्ता उच्च न्यायालय की निगरानी में चल रही है।

सीएम योगी को प्रस्तुत किया गया नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एयरोड्रम लाइसेंस

नोएडा/ लखनऊ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर भारत सरकार की ओर से जारी एयरोड्रम लाइसेंस प्रस्तुत किया । इसके साथ ही जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम पूरा हो गया है। इस लाइसेंस के बाद अब एयरपोर्ट के उद्घाटन और वाणिज्यिक उड़ानों की शुरुआत की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।एयरपोर्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस्टोफ श्नेलमैन समेत वरिष्ठ अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री को परियोजना की प्रगति और आगामी चरणों की जानकारी भी दी। अधिकारियों के अनुसार एयरोड्रम लाइसेंस मिलने के बाद अब नियामकीय स्वीकृतियों की अंतिम प्रक्रिया जारी है।

एयरपोर्ट का एयरोड्रम सिक्योरिटी प्रोग्राम इस समय ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के पास समीक्षा के लिए लंबित है। सुरक्षा से जुड़ी यह मंजूरी मिलते ही एयरपोर्ट प्रबंधन सभी संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय कर औपचारिक उद्घाटन और वाणिज्यिक संचालन की तिथि तय करेगा।गौतमबुद्ध नगर के जेवर में विकसित हो रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देश और दुनिया के प्रमुख शहरों से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। इस एयरपोर्ट को विश्वस्तरीय सुविधाओं के साथ विकसित किया जा रहा है, जहां स्विस दक्षता और भारतीय आतिथ्य का समन्वय देखने को मिलेगा। एयरपोर्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस्टोफ श्नेलमैन हैं। एयरपोर्ट का विकास चार चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण में एक रनवे और एक यात्री टर्मिनल भवन बनाया गया है, जिसकी क्षमता प्रतिवर्ष लगभग 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों की होगी। दूसरे चरण में क्षमता बढ़ाकर 3 करोड़ यात्रियों तक पहुंचाई जाएगी। तीसरे और चौथे चरण में विस्तार के बाद कुल क्षमता 7 करोड़ यात्रियों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।पहले चरण में टर्मिनल भवन का क्षेत्रफल लगभग 1.38 लाख वर्गमीटर है, जिसमें 48 चेक इन काउंटर, 9 सुरक्षा जांच लेन और 9 इमिग्रेशन काउंटर बनाए गए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय लाउंज भी विकसित किए जा रहे हैं। इसके अलावा यहां 10 एयरोब्रिज और 28 विमान पार्किंग स्टैंड की व्यवस्था की गई है। रनवे पर प्रति घंटे लगभग 30 उड़ानों के संचालन की क्षमता विकसित की गई है।

एयरपोर्ट परिसर में आधुनिक कार्गो और लॉजिस्टिक्स हब भी तैयार किया जा रहा है। प्रारंभिक चरण में इसकी क्षमता लगभग 2.5 लाख टन कार्गो प्रतिवर्ष होगी, जिसे आगे चलकर 15 लाख टन तक बढ़ाया जाएगा।तकनीकी दृष्टि से भी यह एयरपोर्ट अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। यहां डिजीयात्रा आधारित बायोमेट्रिक प्रणाली, सेल्फ बैगेज ड्रॉप और डिजिटल पैसेंजर प्रोसेसिंग सिस्टम जैसी व्यवस्थाएं लागू की जा रहीं हैं ताकि यात्रियों को तेज और सहज यात्रा का अनुभव मिल सके। सतत विकास को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट को नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य के साथ विकसित किया जा रहा है।

परिसर में सौर ऊर्जा, वर्षा जल संचयन और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग जैसी सुविधाएं भी विकसित की जा रहीं हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने से दिल्ली-एनसीआर में हवाई यातायात का दबाव कम होगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निवेश, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

उप्र कैबिनेट : यमुना एक्सप्रेस-वे मेडिकल डिवाइस पार्क में निवेश के लिए भूमि सब्सिडी

नोएडा/ लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में मेडिकल डिवाइस निर्माण इकाई स्थापित करने से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत टीआई मेडिकल्स प्राइवेट लिमिटेड को भूमि सब्सिडी प्रदान करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। कंपनी द्वारा गौतमबुद्ध नगर स्थित यमुना एक्सप्रेस-वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यीडा) के मेडिकल डिवाइस पार्क क्षेत्र में 4.48 हेक्टेयर भूमि पर करीब 215.20 करोड़ रुपये के निवेश से चिकित्सा उपकरण निर्माण इकाई स्थापित की जाएगी। यह परियोजना उत्तर प्रदेश की एफडीआई, एफसीआई और फॉर्च्यून इंडिया-500 निवेश प्रोत्साहन नीति-2023 के तहत प्रस्तावित है।

टीआई मेडिकल्स 215 करोड़ रुपये का निवेश कर स्थापित करेगी चिकित्सा उपकरण निर्माण इकाई

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कैबिनेट के निर्णय के अनुसार कंपनी को अनुमन्य सब्सिडी के तहत 14.77 करोड़ रुपये की राशि प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाएगी। यह राशि केंद्र सरकार की मेडिकल डिवाइस पार्क योजना के अंतर्गत पहले से प्राप्त सब्सिडी को समायोजित करने के बाद दी जाएगी। इस निवेश से प्रदेश में मेडिकल डिवाइस निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। यह पहल राज्य को निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायक होगी।

इस परियोजना से संबंधित प्रस्ताव पर पहले विभिन्न स्तरों पर विचार किया गया था। उत्तर प्रदेश की एफडीआई, एफसीआई एवं फॉर्च्यून ग्लोबल 500/फॉर्च्यून इंडिया 500 निवेश प्रोत्साहन नीति-2023 के तहत प्राधिकृत समिति की 5 जुलाई 2024 को हुई बैठक में परियोजना को मंजूरी दी गई थी और कंपनी को 22 जुलाई 2024 को पात्रता प्रमाणपत्र भी जारी किया गया। बाद में 15 मई 2025 को हुई इम्पावर्ड कमेटी की बैठक में सब्सिडी से जुड़े बिंदुओं पर विचार किया गया। मेडिकल डिवाइस पार्क योजना के अंतर्गत कंपनी को पहले से केंद्र सरकार की ओर से सब्सिडी प्राप्त हो चुकी है। इसी आधार पर एफडीआई नीति के तहत अनुमन्य कुल सब्सिडी 41.52 करोड़ में से पहले प्राप्त सब्सिडी घटाकर शेष 14.77 करोड़ की राशि यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) द्वारा कंपनी को प्रतिपूर्ति के रूप में देने का प्रस्ताव तैयार किया गया, जिसे अब मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिल गई है।

फोनरवा की विशेष पहल, 15 मार्च को शहर में चलेगा स्वच्छता अभियान

नोएडा। मंगलवार को फैडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (फोनरवा) की कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। बैठक में समिति द्वारा अन्य विषयों के साथ-साथ यह निर्णय लिया गया कि 15 मार्च को फोनरवा, विभिन्न आरडब्ल्यूए तथा नोएडा प्राधिकरण के सहयोग से नोएडा शहर में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में शहर के विभिन्न सेक्टरों की आरडब्ल्यूए सक्रिय रूप से भाग लेंगी।

पुलिस विभाग एवं प्रशासन से भी कहा गया है कि वे पुलिस चौकियों, थानों तथा अन्य सरकारी कार्यालयों में भी स्वच्छता अभियान चलाकर इस पहल को सफल बनाने में सहयोग करें । फोनरवा के महासचिव केके जैन ने बताया कि फोनरवा द्वारा समय-समय पर नोएडा की विभिन्न आरडब्ल्यूए के सहयोग से स्वच्छता एवं साफ-सफाई को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जाते रहे हैं। इन अभियानों का उद्देश्य नागरिकों को स्वच्छता के महत्व से अवगत कराना तथा स्वच्छ, सुंदर एवं स्वस्थ नोएडा के निर्माण में जनभागीदारी को बढ़ावा देना है।

उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत शहर के विभिन्न सेक्टरों, आवासीय सोसायटियों, बाजारों, पार्कों एवं सार्वजनिक स्थलों पर विशेष साफ-सफाई की जाएगी। साथ ही नागरिकों को कचरा पृथक्करण, प्लास्टिक के कम उपयोग तथा सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखने के लिए भी जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह अभियान न केवल शहर की स्वच्छता को बेहतर बनाएगा, बल्कि नागरिकों में स्वच्छता के प्रति दीर्घकालिक जागरूकता भी विकसित करेगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जिला जज ने प्रचार वाहन को दिखाई हरी झंडी

नोएडा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गौतमबुद्ध नगर के अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव द्वारा आज राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए प्रचार वाहन को जिला मुख्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मार्च 2026 को प्रातः 10 बजे से जनपद के मुख्यालय एवं समस्त तहसील न्यायालयों में आयोजित की जाएगी।

जनपद न्यायाधीश ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर किया जाएगा। इसके अंतर्गत मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम के वाद, वैवाहिक वाद, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के वाद, दीवानी वाद, एनआई एक्ट व ई-चालान के वाद, आर्बिट्रेशन के वाद, लघु शमनीय वाद, एनआई एक्ट की धारा 138 के वाद, विद्युत अधिनियम के वाद, भू-राजस्व के वाद सहित अन्य प्रकृति के मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सेवा संबंधी मामले, पेंशन के मामले, श्रम से संबंधित प्रकरण, प्री-लिटिगेशन स्तर पर बैंक ऋण के मामले, विद्युत एवं बीएसएनएल के टेलीफोनिक बिल से संबंधित प्रकरणों का भी आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।

जनपद न्यायाधीश ने जनपदवासियों से अपील की है कि वे अपने लंबित मामलों के त्वरित एवं सुलभ निस्तारण के लिए संबंधित न्यायालयों से संपर्क स्थापित करें। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के ई-मेल dlsa.gbnnoida@gmail.com अथवा कार्यालय के मोबाइल नंबर 9716535451 व 7678643985 पर संपर्क कर सकते हैं। इस अवसर पर पीठासीन अधिकारी एमएसीटी कोर्ट वत्सल श्रीवास्तव, अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश पोक्सो-द्वितीय विजय कुमार हिमांशु, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण षष्टम प्रतिक्षा नागर, अपर जिला जज-प्रथम सुनील कुमार, अपर जिला जजअधिवेशेष न्यायधीश पोक्सो विकास नागर, अपर जिला जज-शिवानी त्यागी, सिविल जज जू.डि. अंकिता सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहें।

1445 छात्रों ने छोडी यूपी बोर्ड की परीक्षा

नोएडा। जनपद में 60 केंद्रों पर यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा मंगलवार को हुई। परीक्षा दो पालियों में आयोजित की गई। पहली पाली में हाईस्कूल की चित्रकला विषय की परीक्षा हुई और इंटरमीडिएट की कृषि गणित, कृषि रसायन विज्ञान विषय की परीक्षा हुई। दूसरी पाली में इंटरमीडिएट की गृह विज्ञान और व्यवसायिक अध्ययन विषय की परीक्षा हुई। पहली पाली में हाईस्कूल की चित्रकला विषय की परीक्षा में 20963 में से 19706 छात्र मौजूद रहे। 1257 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी। इंटरमीडिएट की कृषि गणित और रसायन विज्ञान विषय की परीक्षा में 246 में से 237 छात्रों ने परीक्षा दी, 9 छात्रों ने परीक्षा नहीं दी। दूसरी पाली में इंटरमीडिएट की गृह विज्ञान और व्यवसायिक अध्ययन विषय की परीक्षा में 3625 में से 3446 छात्रों ने परीक्षा दी, 179 छात्रों ने परीक्षा छोड़ी। केंद्र से परीक्षा देकर निकल रहे छात्रों ने प्रश्नपत्र को आसान बताया। छात्रों ने बताया कि बहुविक्लपीय प्रश्नों में बेहद आसान थे, लेकिन सेक्शन सी के बड़े प्रश्नों के उत्तर लिखने में समय लगा, हालांकि छात्रों का कहना था कि अधिकांश प्रश्न पाठ्यक्रम के अनुसार आने से आसानी हुई।केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की कई विषयों की परीक्षा मंगलवार को आयोजित हुई। सीबीएससी में कक्षा 10वीं की फ्रेंच विषय की परीक्षा हुई, जबकि कक्षा 12वीं में कई विषयों की परीक्षा हुई, जिसमें खाद उत्पाद, पुस्तकालय - सूचना विज्ञान, कार्यालय निर्माता - अभ्यास, प्रारंभिक बाल्यावस्था - शिक्षा जैसे विषय शामिल रहें।

फर्जी रिक्रूटमेंट सेंटर का पर्दाफाश, 4 महिलाओं समेत 6 शातिर गिरफ्तार

नोएडा। देश और विदेशों में क्रूज शिप पर नौकरी दिलाने के नाम धोखाधड़ी करने वाले एक अंतरराष्ट्रीय रैकेट का थाना सेक्टर-113 पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने सेक्टर-73 स्थित एंथूरियम बिजनेस पार्क में छापेमारी कर एक फर्जी रिक्रूटमेंट सेंटर से 2 पुरुषों और 4 महिलाओं समेत कुल 6 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह सोशल मीडिया पर लुभावने विज्ञापन देकर बेरोजगार युवाओं को अपना शिकार बनाता था। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से 7 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 5 मॉनिटर, 5 कीबोर्ड, 5 सीपीयू, 04 माउस, 1 राउटर, 2 मोहर, 2 चेकबुक, 2 सिम कार्ड, 1 एटीएम कार्ड तथा अन्य दस्तावेज बरामद किया है। एडिशनल डीसीपी नोएडा मनीषा सिंह ने बताया कि थाना सेक्टर-113 पुलिस ने मैनुअल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देश-विदेश में क्रूज आदि में नौकरी दिलाने का WE ARE HIRING नामक विज्ञापन चलाकर धोखाधड़ी करने वाले 6 अभियुक्त सरीम खान पुत्र नफीस अहमद, शोएब खान पुत्र नजररुद्दीन, रितिका पुत्री राजीव गुप्ता, मन्तसा अब्बासी पुत्री इकबाल अहमद, फातिमा पुत्री गुलाम गोस सिद्दकी तथा खुशी उर्फ खुशबू पुत्री शकूर खां को एंथूरियम बिजनेस पार्क सेक्टर-73 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस की गिरफ्त में आये सभी अभियुक्त अंतरराष्ट्रीय ठग रैकेट के सदस्य है जो देश-विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवाओं को अपना शिकार बनाता है। उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान अभियुक्त सरीम खान व शोएब खान द्वारा बताया गया कि वे रिक्रूटमेंट सेंटर RECRUITE SERVICE कम्पनी के फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म परWE ARE HIRING के पेड एड चलाकर इच्छुक लोगों से फॉर्म भरवाते और उनकी डिटेल्स लेकर देश-विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 40 से 60 हजार रुपये वसूलते थे। इसके बाद फर्जी जोइनिंग लेटर ईमेल के माध्यम से भेजकर धोखाधड़ी करते थे। इस काम के लिए उन्होंने एंथूरियम बिजनेस पार्क, सेक्टर-73, नोएडा में एक ऑफिस किराए पर लिया था, जहां उनके अन्य साथी भी मौजूद रहते थे। उन्होंने बताया कि इस गिरोह के अन्य सदस्यों को पुलिस तलाश कर रही है।

एमिटी विश्वविद्यालय में चार दिवसीय वार्षिक कला व डिजाइन कार्यक्रम 'क्रिएटिव 2026' का शुभारंभ

नोएडा। एमिटी विश्वविद्यालय में छात्रों की रचनात्मकता एवं प्रतिभा को मंच प्रदान करने के लिए चार दिवसीय वार्षिक कार्यक्रम 'क्रिएटिव 2026' का आयोजन किया गया। आज से 13 मार्च तक चलने वाले कार्यक्रम में एमिटी स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स के छात्रों द्वारा 400 से अधिक चित्रकारी, एप्लाइड आर्ट, एनिमेशन, विजुअल कम्यूनिकेशन आधारित कलाकृति का प्रदर्शन किया गया। जिसका शुभारंभ कलाकार अमितावा दास, एमिटी स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स की चेयरपरसन दिव्या चौहान, कलाकार सुधांशु सुतार, वाइस चांसलर डा बलविंदर शुक्ला, डा प्रदीप जोशी द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर डा वरूण सहाय ने किया।

कार्यक्रम के दौरान अमितावा दास ने कहा कि छात्रों द्वारा बनाई गई कलाओं और प्रदर्शनियों ने प्रभावित किया है। जो आपकी कठिन मेहनत व शिक्षकों के मार्गदर्शन को दर्शा रहे हैं । यह कला भावनाओं, विचारों और टिप्पणियों को व्यक्त करने का सशक्त माध्यम है। इस प्रकार के मंच छात्रों के अंदर नये विचार उत्पन्न होने में सहायता करेंगे। चेयरपरसन दिव्या चौहान ने कहा कि आज का दिन उपलब्धियों के उत्सव मानने का दिन है। एमिटी के संस्थापक अध्यक्ष डा चौहान ने सदैव विज्ञान और कला को समान महत्व दिया है क्योंकी वे विज्ञान के साथ कला के महत्व को भी जानते है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में एआई और तकनीकी के साथ कला का ज्ञान भी महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम के दौरान कलाकार सुधांशु सुतार ने छात्रों से कहा कि चित्र की व्याख्या करने के लिए भाषा के माध्यम की आवश्यकता नहीं यह हदय को छू जाती है। मन में बैठ जाती है। बिना बोले आंखों से देखकर हम चित्रकला को समझ लेते है। भाषा साहित्यिक रूप में भी आती है जैसे वाल्मीकि, कालीदास और तुलसीदास ने लिखी है।

उन्होंने छात्रों से कहा कि आत्मशुद्धी के लिए पढ़ना सीखे और स्वयं की भाषा को समझना आवश्यक है। हम स्वेज नहर के बारे में जानते है किंतु गांव की नदी के बारे में नहीं । हमें विश्व में भारतीय संस्कृति को अपनी कला के माध्यम से सभी तक पहुंचाना है। एमिटी विश्वविद्यालय के ग्रुप एडिशनल प्रो वाइस चांसलर डा प्रदीप जोशी ने बताया कि आज के कार्यक्रम में एमिटी स्कूल ऑफ फाइन आर्टर्स के हर वर्ष के सभी छात्रों द्वारा लगभग 400 से अधिक चित्रकारी, एप्लाइड आर्ट, एनिमेशन, विजुअल कम्यूनिकेशन आधारित कलाओं को प्रस्तुत किया गया है। इस कार्यक्रम में एमिटी स्कूल ऑफ परफॉरमिंग आर्ट्स के द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति, 'भारत में फैशन उद्योग- समावेशी फैशन' पर, ''विकसित भारत के लिए टेक्निकल टेक्साटइल में नवाचार'' पर अंर्तराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त चार दिवसीय कार्यक्रम में एमिटी स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के छात्रों द्वारा डिजाइन कलेक्शन प्रस्तुति - फैशन शो' का आयोजन किया जायेगा।

डीटीसी के बेड़े में 200 नई ईवी बसें होंगी शामिल: परिवहन मंत्री

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने मंगलवार को परिवहन विभाग और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (डीटीसी) के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें राजधानी में इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े के विस्तार, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रमुख ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की गई।

समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि दिल्ली में अभी कुल 4000 से अधिक ईवी बसों का संचालन हो रहा है और इसी महीने मार्च में और 200 नई इलेक्ट्रिक बसों को बेड़े में शामिल किया जाएगा, जिससे दिल्ली का ईवी बस प्लीट और शहर का क्लीन मोबिलिटी नेटवर्क और ज्यादा मजबूत होगा। इस साल के आखिर तक राजधानी दिल्ली का इलेक्ट्रिक बस बेड़ा 7,500 बसों तक पहुंचने का लक्ष्य है, जो दिल्ली के सस्टेनेबल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। परिवहन मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली के ईवी फ्लीट को मजबूत करना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है ताकि पर्यावरण के अनुकूल और यात्रियों के लिए बेहद सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी की समीक्षा करते हुए परिवहन मंत्री को बताया गया कि दिल्ली के 44 बस डिपो में इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया गया है।

इसके अलावा पीएम ई-ड्राइव फेज-I और फेज-II पहल के तहत अभी 36 डिपो में ईवी चार्जिंग नेटवर्क डेवलप किए जा रहे हैं, जो आने वाले महीनों में दिल्ली के इलेक्ट्रिक बस फ्लीट को बढ़ाने में और गति प्रदान करेंगे।

बैठक में प्रमुख परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि दिल्ली सरकार भलस्वा में लगभग 20 एकड़ भूमि पर नया डीटीसी अंतरराज्यीय बस टर्मिनल बनाने की योजना बना रही है, जो उस भूमि पर प्रस्तावित है जिसे लैंडफिल साइट से रिक्लेम किया जा रहा है। प्रस्तावित टर्मिनल से शहर के उत्तरी हिस्से में अंतरराज्यीय बस कनेक्टिविटी और यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है। मंत्री ने विभाग को यह भी निर्देश दिया कि वह अर्बन एक्सटेंशन रोड-II (यूईआर-II) कॉरिडोर पर एक नया डीटीसी डिपो बनाने के लिए फ़ीज़िबिलिटी असेसमेंट करे, ताकि इस क्षेत्र में तेजी से हो रहे शहरी विस्तार और बढ़ती परिवहन मांग को ध्यान में रखते हुए बेहतर ट्रांसपोर्ट सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। इसके अलावा माननीय मंत्री महोदय ने अधिकारियों को बुराड़ी में मौजूदा बस डिपो को अपग्रेड करने का निर्देश दिए, ताकि ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके और बढ़ते इलेक्ट्रिक बस फ्लीट को बेहतर समर्थन मिल सकेगा।

अधिकारियों ने परिवहन मंत्री को यह भी बताया कि हाल ही में नंद नगरी और तेहखंड में बनाने वाले ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) अप्रैल में आम लोगों के लिए चालू होने की उम्मीद है, जिससे गाड़ी की फिटनेस टेस्टिंग का इकोसिस्टम मजबूत होगा और सड़क सुरक्षा स्टैंडर्ड्स के अनुपालन को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। परिवहन मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मॉडर्न बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ईवी बस फ्लीट का विस्तार, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और नए ट्रांसपोर्ट टर्मिनल राजधानी दिल्ली के लिए एक स्वच्छ और ज्यादा कुशल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

जल शक्ति मंत्री पाटिल ने एनडीएसए के नए कार्यालय का किया उद्घाटन

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने मंगलवार को नई दिल्ली के आरके पुरम (वेस्ट ब्लॉक II) में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने देश में बांधों की सुरक्षा और निगरानी को आधुनिक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म और एआई-आधारित प्रणालियों की शुरुआत की। सीआर पाटिल ने बताया कि मानसून के पहले और बाद में हर साल लगभग 13 हजार निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की जाती हैं। उन्होंने जोर दिया कि नेट्रा (एनडीएसए इंजन फॉर ट्रैकिंग एंड रिव्यू यूजिंग एआई) और बांध सुरक्षा डेटा का भंडार डीएचएआरएमए जैसे डेटाबेस में एआई को शामिल करने से इस विशाल डेटा का सटीक विश्लेषण संभव होगा जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार होगा।

मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि नया कार्यालय और ये आधुनिक डिजिटल उपकरण देश के जल बुनियादी ढांचे को सुरक्षित रखने में मील का पत्थर साबित होंगे। इस मौके पर बांध सुरक्षा प्रशासन को मजबूत करने के लिए कई तकनीकों का शुभारंभ किया गया। इनमें एआई आधारित ट्रैकिंग इंजन नेट्रा जीआईएस आधारित एनडीएसए की नई वेबसाइट सी-डैक द्वारा विकसित राष्ट्रीय बांध सुरक्षा दर्पण और सीडब्ल्यूसी सौर ऊर्जा संयंत्र का दूरस्थ शुभारंभ शामिल है।समारोह में जल शक्ति राज्य मंत्री राज भूषण चौधरी, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा पुनर्जीवन विभाग के सचिव वी.एल. कंथा राव केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के अध्यक्ष अनुपम प्रसाद और एनडीएसए के अध्यक्ष अनिल जैन सहित मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

संक्षिप्त खबरें

आठवीं कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म, आरोपी फरार

नई दिल्ली। शालीमार बाग इलाके में आठवीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने सोमवार को दुष्कर्म एवं पोक्सो की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अभी आरोपी की तलाश की जा रही है। जानकारी के अनुसार, 13 वर्षीय पीड़िता परिवार सहित शालीमार बाग इलाके में रहती है। पीड़िता स्थानीय निजी स्कूल में आठवीं कक्षा में पढ़ती है। परिवार के पड़ोस में 24 वर्षीय अनिल (परिवर्तित नाम) भी रहता है। आरोपी अनिल पड़ोसी है। वह अक्सर पीड़िता के घर आता-जाता था। शनिवार को पीड़िता के माता-पिता फैक्टरी में काम करने के लिए गए थे। इसी दौरान आरोपी ने घर में घुसकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मेडिकल और काउंसलिंग के बाद केस दर्ज कर लिया है। एसआई कविता की टीम आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है।

युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग, हालत गंभीर

नई दिल्ली। अंबेडकर नगर के मदनगीर इलाके में सोमवार रात एक युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी गईं। गंभीर रूप से घायल युवक को परिजनों ने एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। पुलिस के अनुसार, 30 वर्षीय निखिल नागर उर्फ निक्की अपने परिवार के साथ मदनगीर में रहता है और घर के पास ही चिकन की दुकान चलाता है। सोमवार रात करीब साढ़े आठ बजे वह दुकान पर मौजूद था। इसी दौरान बाइक सवार कुछ युवक वहां पहुंचे और उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। गोलियों की आवाज सुनकर इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने निखिल को निजी वाहन से एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है।

स्वच्छ पेयजल भी नहीं दे पा रही सरकार: कांग्रेस

नई दिल्ली। दिल्ली कांग्रेस ने कहा कि राजधानी के कई इलाकों में गंदे पानी की आपूर्ति हो रही है। भाजपा सरकार के एक साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन वह इस मुद्दे पर आंखें बंद करके बैठी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि भाजपा सरकार दिल्ली की जनता को स्वच्छ पेयजल तक मुहैया नहीं करा पा रही है। पूर्वी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, बाहरी दिल्ली समेत कई इलाकों में गंदे पानी की आपूर्ति हो रही है। यादव ने कहा कि दिल्ली के मधु विहार, आईपी एक्सटेंशन, मंडावली, पटपड़गंज क्षेत्र के घरों में दिल्ली जल बोर्ड के पानी में कीड़े निकल रहे हैं।

उत्तम नगर हिंसा: आरोपियों के घर बुलडोजर कार्रवाई पर दिल्ली हाई कोर्ट की अंतरिम रोक

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तम नगर हत्याकांड में शामिल आरोपितों के परिवार को राहत दी है। जस्टिस अमित बंसल की बेंच ने बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई कल यानि 11 मार्च को होगी। उच्च न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को बुलडोजर जैसी कोई भी कार्रवाई करने से रोकने का निर्देश दिया।

आज सुनवाई के दौरान दिल्ली नगर निगम ने कोर्ट से इस मामले पर 11 मार्च को सुनवाई करने की मांग की। तब कोर्ट ने कहा कि आज शाम से लेकर 11 मार्च की सुबह तक कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। दरअसल, चार मार्च को होली के दौरान पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण भुटौलिया नामक 26 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद दिल्ली नगर निगम ने 8 मार्च को इस मामले के एक आरोपित के घर के कुछ अवैध हिस्सों को ध्वस्त कर दिया था। इस मामले में आरोपित मुस्लिम समुदाय का है, जिसकी वजह से इसे सांप्रदायिक रंग दिया गया। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने सोहैल और अयान से पूछताछ की थी। उच्च न्यायालय में आरोपित सोहैल, अयान की मां शहनाज और एक अन्य आरोपित इमरान ऊर्फ बंटी की मां जरीना ने याचिका दायर की है। इन याचिकाओं में कहा गया है कि दिल्ली नगर निगम ने एफआईआर दर्ज होते ही मनमाने तरीके से मकान को गिराने की कार्रवाई की है।

याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत और संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 300ए का उल्लंघन है। दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई उच्चतम न्यायालय के फैसले और दिशा-निर्देशों का भी उल्लंघन है।

जींद फैक्ट्री हादसे में 7 मजदूरों की मौत पर केवाईएस का हरियाणा भवन पर प्रदर्शन

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। क्रांतिकारी युवा संगठन (केवाईएस) ने हरियाणा के जींद जिले में गुलाल फैक्ट्री में हुई सात मजदूरों की मौत के विरोध में दिल्ली स्थित हरियाणा भवन के बाहर प्रदर्शन किया। संगठन ने इस घटना को साधारण हादसा नहीं बल्कि सुरक्षा इंतजामों की कमी के कारण हुई गंभीर आपराधिक लापरवाही बताया। बीते शनिवार को जींद जिले के सफीदों में स्थित एक गुलाल बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने से सात महिला मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई अन्य मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि फैक्ट्री में काम करने वाले अधिकांश मजदूर महिलाएं थीं और वहां रंग-गुलाल तैयार करने में बारूद और रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता था। आग लगने के बाद बारूद और केमिकल के कारण लपटें तेजी से फैल गईं।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार फैक्ट्री में सुरक्षा के न्यूनतम इंतजाम भी मौजूद नहीं थे। आग लगने के समय फैक्ट्री का गेट बंद था, जिससे मजदूर बाहर नहीं निकल सके और कई महिलाएं जान बचाने के लिए छत से कूदने को मजबूर हो गईं। इस घटना में चार महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। कई मजदूर अभी भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। संगठन का आरोप है कि ज्वलनशील रसायनों के साथ काम करने के बावजूद फैक्ट्री में न तो अग्निशमन के पर्याप्त साधन थे और न ही श्रम कानूनों के तहत आवश्यक सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था। इसके बावजूद अभी तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होना प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है। केवाईएस ने कहा कि देश में इस तरह की घटनाएं लगातार इसलिए हो रही हैं क्योंकि सरकारें उद्योगपतियों के हितों को प्राथमिकता देती हैं और श्रम कानूनों का खुलेआम उल्लंघन होता है। संगठन का आरोप है कि कई फैक्ट्रियों में सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया जाता और निरीक्षण व्यवस्था लगभग समाप्त हो चुकी है। दुर्घटनाओं के बाद भी मालिकों पर अक्सर केवल आपराधिक लापरवाही जैसी हल्की धाराओं में मामला दर्ज किया जाता है, जिससे दोषी आसानी से बच निकलते हैं। संगठन ने कहा कि यह हादसा ऐसे समय हुआ जब दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा था, जो मेहनतकश महिलाओं की वास्तविक स्थिति को उजागर करता है। केवाईएस का कहना है कि महिलाओं की वास्तविक मुक्ति केवल नारों या सरकारी कार्यक्रमों से नहीं बल्कि सुरक्षित कार्यस्थल, सम्मानजनक मजदूरी और श्रम अधिकारों की गारंटी से ही संभव है।

केवाईएस ने हरियाणा सरकार की उदासीनता की कड़ी निंदा करते हुए हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है। इस संबंध में संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को रेजिडेंट कमिश्नर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। संगठन ने मामले की स्वतंत्र न्यायिक जांच कराने, फैक्ट्री मालिकों और जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों पर गैर-इरादतन हत्या के बजाय हत्या की धारा के तहत सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। संगठन ने मृतक मजदूरों के परिवारों को कम से कम 50 लाख रुपये मुआवजा देने, परिवार के एक सदस्य को स्थायी नौकरी देने और सभी घायलों का मुफ्त तथा उच्चस्तरीय इलाज सुनिश्चित करने की भी मांग उठाई है। साथ ही हरियाणा में चल रही अवैध और असुरक्षित फैक्ट्रियों की तत्काल जांच कर उन्हें बंद करने, सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन कराने और श्रम कानूनों में दुर्घटनाओं के मामलों में सख्त दंडात्मक प्रावधान सुनिश्चित करने की मांग की गई है। केवाईएस ने देशभर की मेहनतकश जनता और न्यायप्रिय लोगों से अपील की है कि वे इस घटना के खिलाफ आवाज उठाएं और कामगारों की सुरक्षा तथा श्रम अधिकारों की रक्षा के लिए व्यापक संघर्ष को मजबूत करें।

चिकित्सा क्षेत्र में महिलाओं का समर्पण स्वास्थ्य तंत्र की रीढ़ : रेखा गुप्ता

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में महिलाओं का समर्पण देश के स्वास्थ्य तंत्र की रीढ़ है। चिकित्सा क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को 'वुमन इन मेडिकल प्रोफेशन' कार्यक्रम में कहा कि आज महिलाएं डॉक्टर, सर्जन, शोधकर्ता, नर्स और स्वास्थ्य विशेषज्ञ के रूप में काम कर रही हैं। दिल्ली सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। महिलाओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं, जागरूकता कार्यक्रमों तथा चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि हर महिला को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सर गंगाराम अस्पताल जैसी प्रतिष्ठित संस्थाएं और यहां की समर्पित महिला चिकित्सा पेशेवर समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा स्वस्थ, जागरूक और सशक्त भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेंगी। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में आयोजित इस कार्यक्रम में अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक, चिकित्सा विशेषज्ञ, नर्सिंग स्टाफ और बड़ी संख्या में महिला स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित रहे।

पालतू जानवर कस्टडी मामले में महुआ को नोटिस

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को वकील जय अनंत देहाद्राय की याचिका पर महुआ मोइत्रा से जवाब मांगा है। याचिका में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के हेनरी नाम के पालतू रॉटवाइलर की साझा कस्टडी का मामला खारिज करने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने जिला अदालत के उस आदेश के खिलाफ देहाद्राय की पुनर्विचार याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें इस मुद्दे पर उनकी अर्जी खारिज कर दी गई थी। हालांकि पीठ ने सुनवाई के इस स्तर पर किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मोइत्रा के पूर्व पार्टनर देहाद्राय ने कहा कि उनका मामला कानून के तहत प्रतबंधित है। देहाद्राय ने जिला अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी।

महापौर ने बागवानी अपशिष्ट संग्रह के लिए 48 टिपर ट्रकों को दिखाई हरी झंडी

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने मंगलवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) मुख्यालय में 48 टिपर ट्रकों को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये वाहन पूरी दिल्ली में बागवानी अपशिष्ट के संग्रहण कार्य को गति देंगे।

सीएनजी से चलने वाले इन वाहनों को हरी झंडी दिखाते हुए महापौर ने कहा कि ये 48 टिपर ट्रक हाइड्रोलिक टिपिंग सुविधा से लैस हैं, जिससे सभी जोनों में बागवानी अपशिष्ट के संग्रहण कार्य को काफी बढ़ावा मिलेगा। ये वाहन दिल्ली नगर निगम के पार्कों से उत्पन्न होने वाले बागवानी कचरे के परिवहन में सहायक होंगे। महापौर ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मार्गदर्शन में दिल्ली नगर निगम शहर में नागरिक सुविधाओं को लगातार सुदृढ़ कर रही है। दिल्ली सरकार के साथ समन्वय में कार्य करते हुए राजधानी को देश का सबसे स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इन टिपर ट्रकों की खरीद भारत सरकार के अर्बन डेवलपमेंट फंड (यूडीएफ) के अंतर्गत प्राप्त वित्तीय सहायता से की गई है। इनका उपयोग हरे कचरे के संग्रहण और परिवहन के लिए किया जाएगा, जिसे दिल्ली नगर निगम के हरित अपशिष्ट केन्द्रों, पार्कों आदि तक पहुंचाया जाएगा, जिससे बागवानी अपशिष्ट प्रबंधन को बेहतर बनाया जा सके।

महापौर ने इन नए ट्रकों के परिचालन लाभों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उद्यान विभाग के बेड़े में इन 48 वाहनो के शामिल होने के बाद बागवानी अपशिष्ट संग्रहण वाहनों की कुल संख्या बढ़कर 74 हो जाएगी। इनकी तैनाती से मानवीय श्रम में कमी आएगी तथा बागवानी कार्यों की गति और दक्षता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि नए खरीदे गए ये वाहन सीएनजी ईंधन पर चलते हैं और नवीनतम बीएस-6 उत्सर्जन मानकों का पालन करते हैं, जिससे ये पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ एमसीडी द्वारा प्रदान की जा रही नागरिक सेवाओं को और सुदृढ़ करेंगे। इन वाहनों की गुणवत्ता जांच आईआईटी दिल्ली द्वारा सुनिश्चित की गई है। महापौर ने कहा कि नगर निगम अपने बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और नागरिकों को अधिक स्वच्छ, सुरक्षित और प्रभावी नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।]

इस अवसर पर स्थायी समिति की अध्यक्षा सत्या शर्मा, दिल्ली नगर निगम की उद्यान समिति अध्यक्ष हरीश ओबरॉय, निगमायुक्त संजीव खिरवार, अतिरिक्त आयुक्त तथा अन्य अतिथि उपस्थित रहे।

बौद्धिक संपदा अपराधों पर सख्ती के लिए आउटर नॉर्थ जिला पुलिस को 'बेस्ट पुलिस यूनिट' अवॉर्ड

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस के आउटर नॉर्थ जिले को बौद्धिक संपदा (आईपी) अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए प्रतिष्ठित 'बेस्ट पुलिस यूनिट' अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है।

यह सम्मान 9 मार्च 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आउटर नॉर्थ जिले के डीसीपी हरेश्वर स्वामी (आईपीएस) को ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और एक लाख रुपये की नकद राशि देकर प्रदान किया। आउटर नॉर्थ जिला पुलिस ने नकली और कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाले उत्पादों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करते हुए कई छापेमारी की और बड़ी मात्रा में नकली सामान जब्त किया। पुलिस की इन कार्रवाइयों से ऐसे कई अवैध नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ, जो नकली उत्पादों के निर्माण और वितरण में शामिल थे।

यह उपलब्धि डीसीपी हरेश्वर स्वामी के नेतृत्व में संयुक्त पुलिस आयुक्त विजय सिंह, विशेष आयुक्त रविंद्र यादव और दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा के मार्गदर्शन में हासिल हुई। आउटर नॉर्थ जिला पुलिस का कहना है कि आगे भी बौद्धिक संपदा से जुड़े अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि वैध व्यापारियों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके।

संपादकीय

युद्ध ने बिगाड़ा चीन का खेल

चीन को अभी तक मध्य पूर्व के युद्ध का झटका नहीं लगा है। लेकिन इसका हल्का असर उस तक पहुंचा जरूर है। फिलहाल चीन के पास कई महीने के लिए तेल का पर्याप्त भंडार है। इसके बाद जरूरत पड़ने पर वह पड़ोसी रूस से मदद ले सकता है। लेकिन चीन यह भी सोच रहा है कि लंबे समय में इस युद्ध का क्या असर होगा? न सिर्फ मध्य पूर्व में उसके निवेश पर बल्कि उसकी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं पर भी। चीन इस समय कई आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। जैसे कम घरेलू खपत, लंबे समय से चल रहा संपत्ति संकट और स्थानीय सरकारों पर भारी । वहीं हाल में चीन ने अपने सालाना आर्थिक विकास लक्ष्य को घटकर 1991 के बाद के सबसे निचले स्तर पर कर दिया है। हालांकि इसके साथ ही चीन हाईटेक और नवीकरणीय ऊर्जा उद्योगों के तेज विकास पर भी काम कर रहा है। चीन को उम्मीद थी कि वह निर्यात बढ़ा कर अपने आर्थिक संकट से उबर सकता है लेकिन पिछले एक साल से वह अमेरिका के साथ वह व्यापार समझौते में उलझा हुआ है। अब उसे मध्य पूर्व में अस्थिरता का खतरा भी झेलना पड़ सकता है। जबकि वही क्षेत्र उसके प्रमुख समुद्री व्यापार मार्गों और ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा स्रोत है। विशेषज्ञों के मुताबिक युद्ध अगर लंबा चला है तो इसका असर और गंभीर हो सकता है खासकर अगर हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही आगे भी बाधित रहती है। लंदन स्थित रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञ फिलिप शेटलर जॉन्स कहते हैं कि अगर मध्य पूर्व में लंबे समय तक स्थिरता बनी रहती है तो इसका असर उन दूसरे क्षेत्रों पर भी पड़ेगा जो चीन के लिए महत्वपूर्ण हैं। अफ्रीका की कई अर्थव्यवस्थाओं को खाड़ी देशों से लगातार निवेश मिलता रहा है। अगर यह निवेश रुकता है तो इससे व्यापार अस्तित्व पैदा हो सकती है। जिससे चीन के लंबे समय के हितों को भी नुकसान पहुंच सकता है। यानी चीन के वैश्विक निवेश और बाजार भी इस लंबे युद्ध से प्रभावित हो सकते हैं। इन दिनों चीन बेहद सावधानी से कदम बढ़ा रहा है। इसकी एक बड़ी वजह अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जो इस महीने के अंत में चीन आने वाले हैं। चीन ने अब तक अमेरिका और इजराइल की आलोचना करते हुए भी ट्रंप पर सीधा हमला नहीं किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन इस मुलाकात से यह समझने की कोशिश करेगा कि अमेरिका ताइवान जैसे मुद्दों पर क्या रुख अपनाएगा।

धूम्रपान निषेध दिवस

निकोटीन का जहर और समाज का मौन संकट

वैश्विक रिपोर्टों के अनुसार 13 से 15 वर्ष की आयु के लगभग 3.7 करोड़ बच्चे किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। ई-सिगरेट और अन्य नए निकोटीन उत्पादों ने इस समस्या को और जटिल बना दिया है। आकर्षक पैकेजिंग, फ्लेवर और डिजिटल मार्केटिंग के जरिए इन उत्पादों को युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाने की कोशिश की जा रही है। विज्ञापन प्रतिबंधों के बावजूद सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से युवाओं को लक्ष्य बनाकर प्रचार किया जाता है। इस कारण किशोरों में तंबाकू की लत तेजी से फैल रही है, जो भविष्य में गंभीर स्वास्थ्य संकट का रूप ले सकती है। तंबाकू के दुष्प्रभाव केवल कैंसर तक सीमित नहीं हैं। यह शरीर के लगभग हर अंग को नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान फेफड़ों के कैंसर का प्रमुख कारण है और दुनिया में होने वाली फेफड़ों के कैंसर से लगभग 85 प्रतिशत मौतें धूम्रपान के कारण होती हैं। इसके अलावा तंबाकू हृदय रोग, स्ट्रोक, दमा, ब्रोंकाइटिस और कई अन्य श्वसन संबंधी बीमारियों को जन्म देता है। लंबे समय तक तंबाकू का सेवन करने से मुंह, गले, पेट, लीवर और आंतों के कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। तंबाकू की समस्या भारत में भी काफी गंभीर है।

-योगेश कुमार गोयल-

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है लेकिन दुर्भाग्य से धूम्रपान और तंबाकू की लत इस अमूल्य धन को तेजी से नष्ट कर रही है। हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को 'नो स्मोकिंग डे' मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों को धूम्रपान की आदत छोड़ने के लिए प्रेरित करना और समाज को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना है। इस वर्ष यह दिवस 11 मार्च को मनाया जा रहा है। यह एक ऐसा अवसर है, जब लोग अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकते हैं और धूम्रपान मुक्त जीवन की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। हर वर्ष इस दिन एक विशेष थीम के साथ लोगों को तंबाकू से दूर रहने का संदेश दिया जाता है। इस वर्ष का संदेश है 'धूम्रपान से मुक्त जीवन की शुरुआत एक धूम्रपान-मुक्त दिन से होती है।' इसका अर्थ स्पष्ट है कि यदि कोई व्यक्ति केवल एक दिन भी धूम्रपान से दूरी बना ले तो वह आगे चलकर इसे पूरी तरह छोड़ने की दिशा में पहला कदम उठा सकता है।

तंबाकू और निकोटीन की लत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार तंबाकू के कारण हर वर्ष लगभग 80 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। इनमें से करीब 70 लाख लोग सीधे धूम्रपान करने वाले होते हैं जबकि लगभग 12 लाख लोग ऐसे होते है, जो स्वयं धूम्रपान नहीं करते लेकिन दूसरों के धुएं के संपर्क में आने के कारण गंभीर बीमारियों का शिकार बन जाते हैं। यह स्थिति बताती है कि धूम्रपान केवल करने वाले व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उसके आसपास रहने वाले परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है। हाल के वर्षों में देखा गया है कि दुनिया के कई देशों में धूम्रपान करने वालों की संख्या में कमी आई है लेकिन इसके बावजूद चिंता का विषय यह है कि युवाओं और किशोरों में तंबाकू के उपयोग की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है।

वैश्विक रिपोर्टों के अनुसार 13 से 15 वर्ष की आयु के लगभग 3.7 करोड़ बच्चे किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। ई-सिगरेट और अन्य नए निकोटीन उत्पादों ने इस समस्या को और जटिल बना दिया है। आकर्षक पैकेजिंग, फ्लेवर और डिजिटल मार्केटिंग के जरिए इन उत्पादों को युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाने की कोशिश की जा रही है। विज्ञापन प्रतिबंधों के बावजूद सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से युवाओं को लक्ष्य बनाकर प्रचार किया जाता है। इस कारण किशोरों में तंबाकू की लत तेजी से फैल रही है, जो भविष्य में गंभीर स्वास्थ्य संकट का रूप ले सकती है। तंबाकू के दुष्प्रभाव केवल कैंसर तक सीमित नहीं हैं। यह शरीर के लगभग हर अंग को नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान फेफड़ों के कैंसर का प्रमुख कारण है और दुनिया में होने वाली फेफड़ों के कैंसर से लगभग 85 प्रतिशत मौतें धूम्रपान के कारण होती हैं। इसके अलावा तंबाकू हृदय रोग, स्ट्रोक, दमा, ब्रोंकाइटिस और कई अन्य श्वसन संबंधी बीमारियों को जन्म देता है। लंबे समय तक तंबाकू का सेवन करने से मुंह, गले, पेट, लीवर और आंतों के कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। तंबाकू की समस्या भारत में भी काफी गंभीर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के 25 करोड़ से अधिक लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं। इनमें अधिकांश पुरुष हैं लेकिन महिलाओं में भी इसका उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। भारत में तंबाकू सेवन के कई रूप प्रचलित हैं, जैसे खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा और सुपारी के साथ तंबाकू का सेवन।

इन उत्पादों की आसान उपलब्धता और कम कीमत के कारण लोग जल्दी इसकी लत के शिकार हो जाते हैं। विभिन्न शोधों में यह भी सामने आया है कि तंबाकू से होने वाली बीमारियों का इलाज बहुत महंगा होता है। यदि तंबाकू के उपयोग को नियंत्रित नहीं किया गया तो आने वाले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका आर्थिक बोझ बहुत अधिक बढ़ सकता है। मुंह के कैंसर के मामलों में भारत पहले से ही दुनिया के कई देशों से आगे है और इसका मुख्य कारण तंबाकू तथा गुटखे का व्यापक उपयोग है। धूम्रपान केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक और सामाजिक समस्याओं को भी जन्म देता है। तंबाकू की लत व्यक्ति को धीरे-धीरे निर्भर बना देती है। कई युवाओं में यह लत अवसाद, चिंता और आत्मविश्वास की कमी जैसी मानसिक समस्याओं को भी जन्म देती है। जब किशोरावस्था में यह आदत लग जाती है तो उसे छोड़ना बेहद कठिन हो जाता है और इसका प्रभाव उनके पूरे जीवन पर पड़ता है। धूम्रपान के खतरों को देखते हुए समाज में व्यापक जागरूकता की आवश्यकता है। सरकारों ने तंबाकू नियंत्रण के लिए कई कानून बनाए हैं, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया है और तंबाकू उत्पादों पर चेतावनी संदेश भी अनिवार्य किए हैं। इसके बावजूद केवल कानून से इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। इसके लिए सामाजिक जागरूकता और व्यक्तिगत संकल्प दोनों जरूरी हैं। पत्रकारिता के अपने लंबे अनुभव के दौरान मैंने नशे के दुष्प्रभावों पर व्यापक अध्ययन किया है। वर्ष 1993 में मेरी पुस्तक 'मौत को खुला निमंत्रण' प्रकाशित हुई थी, जिसमें तंबाकू और अन्य नशों से होने वाले भयानक परिणामों का विस्तार से उल्लेख किया गया था। उस समय भी यह चेतावनी दी गई थी कि यदि समाज ने समय रहते नशे के खिलाफ जागरूकता नहीं बढ़ाई तो इसके दुष्परिणाम आने वाली पीढ़ियों को भुगतने पड़ेंगे। आज तीन दशक बाद भी यह चिंता उतनी ही प्रासंगिक दिखाई देती है।

बहरहाल, नो स्मोकिंग डे हमें याद दिलाता है कि जीवन का हर पल अमूल्य है और इसे किसी भी तरह की लत के कारण बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। धूम्रपान छोड़ना कठिन अवश्य है लेकिन असंभव नहीं। यदि व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर ले और परिवार तथा समाज का सहयोग मिले तो वह आसानी से इस लत से मुक्त हो सकता है। आज जरूरत इस बात की है कि हम स्वयं भी धूम्रपान से दूर रहें और दूसरों को भी इसके खतरों के बारे में जागरूक करें। आखिरकार, एक स्वस्थ समाज की शुरुआत स्वस्थ व्यक्तियों से ही होती है। यदि हम तंबाकू से दूरी बनाकर जीवन को अपनाएं तो न केवल अपना स्वास्थ्य सुरक्षित रख सकते हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर और सुरक्षित वातावरण तैयार कर सकते हैं। इसलिए इस नो स्मोकिंग डे पर संकल्प लें कि तंबाकू का साथ छोड़कर हर सांस को कीमती बनाएंगे और जीवन को स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे।

तीन साल में तीन आईसीसी ट्रॉफी: भारतीय क्रिकेट का स्वर्णिम दौर

- कांतिलाल मांडोत-

भारत अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया टी-20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल भारतीय क्रिकेट के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर तीसरी बार टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ भारत ने केवल एक टूर्नामेंट नहीं जीता, बल्कि लगातार सफलता की ऐसी कहानी लिखी जिसने दुनिया को भारतीय क्रिकेट की ताकत का एहसास करा दिया। पिछले तीन वर्षों में तीन आईसीसी ट्रॉफी जीतना इस बात का प्रमाण है कि टीम इंडिया ने निरंतरता, आत्मविश्वास और सामूहिक मेहनत से सफलता का नया अध्याय रचा है।

भारत की इस शानदार जीत में बल्लेबाजों से लेकर गेंदबाजों तक सभी खिलाड़ियों का योगदान रहा। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 255 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। यह टी-20 वर्ल्ड कप फाइनल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर भी बन गया। इतने बड़े लक्ष्य के सामने न्यूजीलैंड की टीम दबाव में आ गई और पूरी टीम 159 रन पर ही सिमट गई। इस प्रकार भारत ने न केवल जीत दर्ज की बल्कि टी-20 क्रिकेट में अपनी आक्रामक शैली का शानदार प्रदर्शन भी किया। इस ऐतिहासिक जीत का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि भारत ने तीन साल के भीतर तीन आईसीसी ट्रॉफियां जीतने का कारनामा किया है। वर्ष 2024 में भारत ने टी-20 वर्ल्ड कप जीतकर लगभग 17 वर्षों बाद इस खिताब को अपने नाम किया था। इसके बाद 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर टीम ने अपनी लय बरकरार रखी और अब 2026 में फिर से टी-20 वर्ल्ड कप जीतकर विश्व क्रिकेट में अपना दबदबा साबित कर दिया। लगातार दो बार टी-20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारत पहली टीम बन गई है और यह उपलब्धि भारतीय क्रिकेट के स्वर्णिम दौर को दर्शाती है।

टीम इंडिया की सफलता के पीछे केवल प्रतिभा नहीं बल्कि खिलाड़ियों की कठिन मेहनत, अनुशासन और टीम भावना भी है। इस टूर्नामेंट में भारतीय बल्लेबाजों ने जिस आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की, उसने विरोधी टीमों के गेंदबाजों को लगातार दबाव में रखा। पूरे टूर्नामेंट में भारत ने 106 छक्के लगाए, जो किसी भी टी-20 वर्ल्ड कप के एक संस्करण में सबसे अधिक हैं। यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि भारतीय टीम अब केवल तकनीकी रूप से मजबूत ही नहीं बल्कि आक्रामक क्रिकेट खेलने में भी सबसे आगे है। इस शानदार प्रदर्शन में सबसे बड़ा योगदान रहा भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन का। संजू सैमसन ने पूरे टूर्नामेंट में 321 रन बनाए और भारत के लिए एक टी-20 वर्ल्ड कप संस्करण में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इससे पहले यह रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम था, जिन्होंने 2014 में 319 रन बनाए थे। संजू की बल्लेबाजी में आत्मविश्वास, आक्रामकता और जिम्मेदारी का अद्भुत संतुलन दिखाई दिया, जिसने भारत को कई कठिन मैचों में जीत दिलाई। संजू सैमसन की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि उन्होंने बड़े मैचों में शानदार प्रदर्शन किया। सेमीफाइनल और फाइनल जैसे दबाव भरे मुकाबलों में भी उन्होंने अर्धशतक लगाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। पूरे टूर्नामेंट में उनका स्ट्राइक रेट लगभग 200 के आसपास रहा, जो टी-20 क्रिकेट के लिए बेहद प्रभावशाली माना जाता है। उनके इस शानदार प्रदर्शन के कारण उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया।

भारतीय टीम की बल्लेबाजी में इंसान किशन और अभिषेक शर्मा ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईशान किशन ने पूरे टूर्नामेंट में 317 रन बनाए और कई मैचों में तेज शुरुआत देकर टीम को मजबूत आधार दिया। वहीं अभिषेक शर्मा ने फाइनल में केवल 18 गेंदों में अर्धशतक लगाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह से दबाव में ला दिया। टीम इंडिया की गेंदबाजी भी इस टूर्नामेंट में उतनी ही प्रभावशाली रही। भारतीय तेज गेंदबाज जशप्रीत बुमराह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टूर्नामेंट में सबसे अधिक विकेट हासिल किए। फाइनल मैच में उन्होंने केवल 15 रन देकर 4 विकेट लिए और न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। उनकी सटीक लाइन-लेंथ और दबाव में शानदार गेंदबाजी ने भारत की जीत को आसान बना दिया। यही कारण है कि उन्हें फाइनल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी चुना गया।

भारतीय टीम की सफलता में ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या का योगदान भी बेहद महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन किया। हार्दिक ने 200 से अधिक रन बनाए और साथ ही महत्वपूर्ण विकेट भी हासिल किए। सेमीफाइनल में उनके ऑलराउंड प्रदर्शन ने भारत को इंग्लैंड के खिलाफ रोमांचक जीत दिलाई, जिसने टीम का आत्मविश्वास और भी मजबूत कर दिया। फाइनल मुकाबले में शिवम दुबे की छोटी लेकिन विस्फोटक पारी भी बेहद अहम साबित हुई। जब भारत की पारी थोड़ी धीमी पड़ती दिखाई दे रही थी, तब शिवम दुबे ने अंतिम ओवरों में तेज रन बनाकर टीम का स्कोर 255 तक पहुंचा दिया। उनकी केवल 8 गेंदों में 26 रन की पारी ने न्यूजीलैंड के सामने बेहद मुश्किल लक्ष्य खड़ा कर दिया।

इस पूरी सफलता के पीछे टीम के कोच गौतम गम्भीर की रणनीति और मार्गदर्शन भी महत्वपूर्ण रहा। गंभीर पहले खिलाड़ी के रूप में बड़े फाइनल मैचों में शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं और अब कोच के रूप में भी उन्होंने टीम को सफलता दिलाई है। उनकी सोच, रणनीति और खिलाड़ियों पर विश्वास ने टीम को लगातार जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। भारतीय टीम की इस जीत ने पूरे देश में उत्साह और गर्व का माहौल बना दिया। जीत के बाद देशभर में लोगों ने सड़कों पर उतरकर जश्न मनाया। कई जगहों पर आतिशबाजी हुई और लोग तिरंगा लेकर खुशी से झूमते नजर आए। यह जीत केवल खिलाड़ियों की नहीं बल्कि पूरे देश की जीत बन गई। दरअसल, खेल केवल प्रतिभा का नहीं बल्कि मेहनत, धैर्य और टीम भावना का परिणाम होता है। भारतीय खिलाड़ियों ने लगातार अभ्यास, फिटनेस और मानसिक मजबूती के साथ खुद को तैयार किया और कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। यही कारण है कि उनकी मेहनत का फल अब लगातार जीत के रूप में सामने आ रहा है।

टी-20 वर्ल्ड कप 2026 की यह जीत केवल एक ट्रॉफी नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट के आत्मविश्वास और भविष्य की दिशा का प्रतीक है। यह सफलता आने वाली पीढ़ियों के खिलाड़ियों को प्रेरणा देगी कि अगर मेहनत, समर्पण और टीमवर्क के साथ खेला जाए तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। भारतीय क्रिकेट टीम ने इस जीत के साथ दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि वह केवल मजबूत टीम ही नहीं बल्कि विश्व क्रिकेट की नई शक्ति बन चुकी है। खिलाड़ियों की मेहनत, कोच की रणनीति और करोड़ों भारतीयों के समर्थन ने मिलकर यह ऐतिहासिक सफलता संभव बनाई है। यही कारण है कि आज हर भारतीय गर्व से कह सकता है कि यह जीत मेहनत, विश्वास और सपनों की जीत है।

जिनालय के शिखर का महत्व

जिस प्रकार समवशरण के ऊपर अशोक वृक्ष होता है उसी प्रकार मंदिर में अशोक वृक्ष के प्रतीक रूप शिखर बनाया जाता है एवं जो लोग परिस्थितिवश मंदिर नहीं जा पाते तो वह दूर से ही शिखर की वंदना करके पुण्यार्जन कर लेते हैं और यदि ऊपर से देवता आदि के विमान निकलते है तो ऊंचे-ऊंचे शिखर देखकर वे भी जिनालय के दर्शन का लाभ उठा पाते हैं। इसलिए भी मंदिर में शिखर बनाए जाते हैं एवं जैसे अशोक वृक्ष के नीचे जाने पर सारे शोक नष्ट हो जाते हैं उसी प्रकार मंदिर के शिखर के नीचे जाकर (परमात्मा) की उपासना करने से भी सारे शोक नष्ट हो जाते हैं। मंदिर के शिखर प्रकृति, से विशुद्ध परमाणुओं को संग्रहीत कर मंदिर में नीचे पहुंचते हैं, जिससे मंदिर का वातावरण शुद्ध बना रहता है। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मंदिर में शिखर बनाए जाते हैं। कलश मंगल एवं पूर्णता का प्रतीक होते हैं। मानव जब परमात्मा की सतत साधना करता है तो पूर्ण या परमात्मा हो जाता है, मानव का क्रमिक विकास ही परमात्मा हैं जिस तरह से कलश सबसे नीचे बड़ा उसके ऊपर दूसरा उससे छोटा फिर तीसरा उससे छोटा अर्थात क्रम-क्रम से शून्यता की ओर पहुंचता है वैसे ही मनुष्य जैसे-जैसे आकांक्षा, कामना, वासना से छूटता है वैसे ही मनुष्यता को उपलब्ध होकर परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेता है। इसी बात की प्रेरणा हेतु मंदिर के शिखर पर कलश चढ़ाए जाते हैं। मंदिर जी में हो रही भक्ति, पूजन, मंत्र आदि की शब्द वर्गणा को मंदिर के ऊपर की ओर खींचकर ध्वजा के माध्यम से वह पुद्गल शब्द वर्गणा सर्वत्र हवाओं को स्पर्शित होकर व्याप्त होती है और जहां-जहां वह हवा जाती है, वहां-वहां का वातावरण शुद्ध, शांत, सात्विक, धार्मिक होता जाता है। इसलिए कलश के ऊपर ध्वजा लगाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हर दिन लोग मंदिर जाकर भगवान की पूजा करते हैं लेकिन किसी कारण से मंदिर नहीं जा पाते हैं तो शास्त्रों में उनके लिए भी उपाय बताया गया है कि मंदिर ना जाने से भी मंदिर जाने का पुण्य मिलता है। माना जाता है कि मंदिर के अंदर नहीं जा पा रहे हैं तो बाहर से ही मंदिर के शिखर को प्रणाम कर सकते हैं। माना जाता है कि शिखर दर्शन से भी उतना पुण्य मिलता है जितना मंदिर में प्रतिमा के दर्शन करने से मिलता है। शास्त्रों में कई जगह लिखा गया है कि शिखर दर्शनम पाप नाशम। इसका अर्थ है कि शिखर के दर्शन कर लेने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।

धर्मकर्म

आज का इतिहास

1669 - इटली में एटना ज्वालामुखी फटने से 15 हजार लोगों की मौत हुई।
1702 - पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र 'डेली कुरंट' का प्रकाशन शुरू किया गया।
1779 - पहली बार अमेरिकी सेना ने कोर इंजीनियर्स की स्थापना की।
1810 - नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया की मैरी-लुईस से शादी की।
1823 - कॉनकॉर्ड अकादमी, कॉनकॉर्ड, वीटी, संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला सामान्य स्कूल खोला गया।
1843 - एटा कैरिना रात के आकाश में दूसरा सबसे चमकीला तारा बनने के लिए भड़क गया।
1848 - लुई-हिप्पोलीटे लाफोंटेन और रॉबर्ट बाल्डविन कनाडा के प्रांत के पहले प्रधान मंत्री बन गए हैं, जिन्हें लोकतांत्रिक रूप से जिम्मेदार सरकार की एक प्रणाली चुना गया है।
1851 - इतालवी रोमांटिक संगीतकार Giuseppe Verdi के ओपेरा Rigo-letto को पहली बार वेनिस के La Fenice में प्रदर्शित किया गया था।
1864 - इंग्लैंड के शेफ़ील्ड में डेल डाइक डैम में दरार के कारण यह विफल हो गया और इसके परिणामस्वरूप बाढ़ ने 238 लोगों की जान ले ली और 600 से अधिक घरों को नुकसान पहुँचा।
1879 - शाओ ताई, रयूकू साम्राज्य के अंतिम राजा, निरर्थक राज्य जापान द्वारा खारिज कर दिया गया और ओकिनावा प्रान्त बन गया।
1888 - 1888 के ग्रेट ब्लिजार्ड ने उत्तरपूर्वी यूनाइटेडस्टेट्स पर हमला किया, 50 फीट (15 मीटर) से अधिक के स्नोड्रिफ्ट का उत्पादन किया और एक सप्ताह तक लोगों को उनके घरों तक सीमित किया।
1895 - स्पेन के जहाज रीना रीगेंटा के जिब्राल्टर में डूबने से 400 यात्रियों की मौत हुई।
1912 - माइनर्स फेडरेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ने प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की पहल की।
1945 - बर्मा ने ब्रिटिश के 36 वें डिवीजन ममते को बचाया।
1946 - रूशॉल्फ एचओएसएस, ऑशविट्ज़ एकाग्रता शिविर के पहले कमांडेंट, ब्रिटिश सैनिकों द्वारा कब्जा कर लिया गया था।

सोशल मीडिया के ग्रहण से बच्चों और किशोरों को बचाने की कवायद

-मनोज कुमार अग्रवाल-

सोशल मीडिया के जाल में फंसकर बच्चों के पठन पाठन और खेल के मैदान से दूरी के अलावा अपराध और सुसाइड की वारदातों ने चिंता बढ़ा दी हैं। इसी सब के बीच आंध्र प्रदेश और कर्नाटक द्वारा अलग-अलग आयु समूहों में बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है सरकारों द्वारा किया गया यह निर्णय निसंदेह, सराहनीय, साहसिक और स्वाग्तयोग कदम है। बच्चों और किशोरों के बीच सोशल मीडिया का उपयोग किस तेजी से बड़ा है, यह बात छिपी नहीं है।

सूचना, शिक्षा, मनोरंजन और संवाद के अनेक साधन अब हमारी हथेली में मौजूद हैं, लेकिन इस तकनीकी क्रांति का एक दूसरा पहलू भी है, जो विशेष रूप से बच्चों और किशोरों के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। कम उम्र में सोशल मीडिया का बढ़ता उपयोग बच्चों के मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। यही कारण है कि अब राज्य सरकारें इस मुद्दे को गंभीरता से लेने लगी हैं। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। कर्नाटक सरकार ने अपने 2026-27 के बजट में यह पहल करते हुए कहा कि किशोरों को सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों से बचाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। इसी दिशा में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने भी घोषणा की है कि 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर अगले 90 दिनों के भीतर रोक लगा दी जाएगी। यह निर्णय केवल प्रशासनिक कदम नहीं, बल्कि बच्चों के भविष्य और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बढ़ती चिंताओं का संकेत भी है। लेकिन इसके साथ-साथ इससे जुड़ी कई गंभीर चिंताएं भी सामने आई हैं, जैसे मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, पढ़ाई में गिरावट, ऑनलाइन लत और साइबर खतरों का बढ़ना। पिछले कुछ वर्षों र में स्मार्टफोन और इंटरनेट की उपलब्धता ने बच्चों को बहुत कम उम्र में ही सोशल मीडिया से जोड़ दिया है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म बच्चों के दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। कई बच्चे घंटों तक मोबाइल स्क्रीन पर लगे रहते हैं, जिससे उनकी पड़ई, खेलकूद ह और सामाजिक जीवन प्रभावित होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार सोशल मीडिया के संपर्क में रहने से बच्चों में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता नि कम होती है।

वे वास्तविक जीवन की गतिविधियों से दूर होते जाते हैं और डिजिटल दुनिया में अधिक समय बिताने लगते हैं। यही स्थिति धीरे-धीरे डिजिटल लत में बदल जाती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सोशल मीडिया क का अत्यधिक उपयोग बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। अवसाद, चिंता, नींद की कमी और आत्मविश्वास में क गिरावट जैसी समस्याएं बढ़ने लगी हैं। खासकर किशोरों में दूसरों से तुलना क करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जिससे हीन भावना और शरीर की छवि को लेकर असंतोष पैदा होता है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की पहल इसी वैश्विक चिंता का हिस्सा मानी जा सकती है। राज्य सरकारों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किशोरों को डिजिटल दुनिया के नकारात्मक प्रभावों से बचाया जा सके। माता-पिता और शिक्षकों की लंबे समय से यह शिकायत रही है कि बच्चों का बढ़ता स्क्रीन टाइम उनकी पढ़ाई, एकाग्रता और सामाजिक व्यवहार को प्रभावित कर रहा है। सोशल मीडिया पर अत्यधिक समय बिताने से बच्चों की नींद प्रभावित होती है, शारीरिक गतिविधियां कम हो जाती हैं और वास्तविक सामाजिक संबंध कमजोर पड़ने लगते हैं। यहीं कारण है कि बच्चों को बचाने के लिए भारत में कदम उठाने की मांग काफी पहले से हो रही है। हालांकि यह कदम केवल भारत तक सीमित नहीं है। दुनिया के कई देश पहले ही इस दिशा में कठोर कदम उठा चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लागू किया है, जबकि फ्रांस और कुछ यूरोपीय देशों में भी डिजिटल सुरक्षा से जुड़े कड़े नियम बनाए जा रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि यह समस्या वैश्विक स्तर पर गंभीर होती जा रही है। हकिकत यह है कि बच्चों और किशोरों के जीवन में सोशल मीडिया की बढ़ती उपस्थिति ने कई मनोवैज्ञानिक चुनौतियों को जन्म दिया है। इस उम्र में बच्चों का मस्तिष्क तेजी से विकसित हो रहा होता है और वे बाहरी प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सामग्री हमेशा सकारात्मक या सुरक्षित नहीं होती। कई बार बच्चे हिंसक, अश्लील या भ्रामक सामग्री के संपर्क में आ जाते हैं, जिसका उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। कई शोध यह बताते हैं कि जो बच्चे प्रतिदिन तीन घंटे या उससे अधिक समय सोशल मीडिया पर क बिताते हैं, उनमें अवसाद, तनाव और आत्मविश्वास की कमी की समस्या स अधिक देखी जाती है। लगातार दूसरों की जीवनशैली और उपलब्धियों को देखकर बच्चों में तुलना को प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इससे उनमें हीन भावना भी न पैदा हो सकती है। इसके अलावा देर रात तक मोवाइल और सोशल मीडिया प का उपयोग बच्चों की नींद को भी प्रभावित करता है। पर्याप्त नींद न मिलने से उनकी एकाग्रता कम होती है और पढ़ाई में भी गिरावट आती है। लंबे नि समय तक स्क्रीन के सामने रहने से आंखों और मस्तिष्क पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सोशल मीडिया का एक बड़ा खतरा साइबर बुलिंग यानी ऑनलाइन उत्पीड़न भी है। कई बार बच्चे अपने सहपाठियों या अनजान लोगों द्वारा ऑनलाइन अपमान, धमकी या मजाक का शिकार बन जाते हैं। कम उम्र में ऐसी घटनाएं बच्चों के आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती हैं। इंटरनेट की दुनिया में गुमनामी के कारण कई लोग बिना किसी डर के दूसरों को परेशान करते हैं। बच्चे अक्सर यह समझ नहीं पाते कि ऐसी स्थितियों से कैसे निपटना चाहिए। कई मामलों में यह मानसिक तनाव इतना बढ़ जाता है कि बच्चों में अकेलापन, स डर और अवसाद जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। हालांकि बच्चों की सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का विचार सराहनीय है, लेकिन इसका क्रियान्वयन आसान नहीं होगा। आज के समय में मोबाइल नि फोन और इंटरनेट शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण साधन बन चुके हैं। स्कूलों के असाइनमेंट, नोटिस और पढ़ाई पढ़ाई से से जुड़े जुड़े कई कई कार्य क अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही पूरे किए से ही पूरे किए जाते हैं। ऐसे में शैक्षिक उपयोग और मनोरंजन के उपयोग के बीच अंतर करना कठिन हो सकता है। एक और बड़ी चुनौती बच्चों की उम्र का सत्यापन है। इंटरनेट पर यह सुनिश्चित करना कि किसी उपयोगकर्ता की उम्र वास्तव में कितनी है, तकनीकी रूप से जटिल कार्य है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक आदित्य वशिष्ठ द्वारा सांई प्रिंटिंग प्रेस, बी-42 सेक्टर -7 नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश-201301 से मुद्रित व बी-142/2, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065 से प्रकाशित।
संपादकीय एवं संपर्क कार्यालय ए-152 सेक्टर-63, नोएडा-201301 **संपादक - आदित्य वशिष्ठ** कानूनी सलाहकार-पवित्र मोहन शर्मा आर.एन.आई. DELHIN/2012/42452
इस अंक में प्रकाशित सभी समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी एक्ट के अंतर्गत संपादक उत्तरदायी होंगे। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे। e-mail: Jbttimes2021@ gmail. Com

रक्षा मंत्री ने भारतीय सेना के लिए 'मिलिट्री विजन डॉक्यूमेंट' रोडमैप जारी किया

भविष्य की युद्ध चुनौतियों के लिए सेना को आधुनिक, इंटीग्रेटेड और तकनीक से लैस करने पर जोर

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को साउथ ब्लॉक में भारतीय सेना के लिए 'डिफेंस फोर्सेज विजन' रोडमैप जारी किया। यह बड़ा ब्लूप्रिंट हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ने रक्षा बलों को आधुनिक, इंटीग्रेटेड और तकनीक से लैस सेना में बदलने के लिए तैयार किया है, जो 2047 तक भारत के विकसित देश बनने के सपने को पूरा करने में मदद कर सके।

यह डॉक्यूमेंट भविष्य की युद्ध चुनौतियों के लिए ढलने वाली सेना बनाने के लिए इनोवेशन, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और मॉडर्न ट्रेनिंग फ्रेमवर्क के महत्व पर भी जोर देता है। इस विजन डॉक्यूमेंट में सशस्त्र बलों में जरूरी सामरिक सुधारों, क्षमता बढ़ाने और संगठनात्मक बदलावों के बारे में बताया गया है, ताकि बदलते भू-रणनीतिक, तकनीकी और सुरक्षा माहौल से अच्छे से निपटा जा सके। इसमें सेना को एक इंटीग्रेटेड, मल्टी-डोमेन और फुर्तीली फोर्स में बदलने की सोची गई है, जो दुश्मनों को रोकने, हर तरह के झगड़े में जवाब देने और तेजी से बदलते ग्लोबल और रीजनल हालात के बीच बढ़ते स्ट्रेटेजिक हितों की रक्षा करने में काबिल हो। इस विजन का एक मुख्य हिस्सा सेनाओं के बीच तालमेल और तालमेल पर जोर देना है, जिससे प्लानिंग, ऑपरेशन और क्षमता विकास में ज्यादा तालमेल को बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस विजन में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर ध्यान केन्द्रित किया गया है, जो देश की खास सुरक्षा जरूरतों के हिसाब से स्वदेशी तकनीक और समाधान अपनाने को बढ़ावा देता है।

घरेलू रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी क्षमताओं को मजबूत करने से ऑपरेशनल क्षमताओं, संस्थागत सुधारों और रणनीतिक साझेदारी के विकास में सहयोग करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों की जटिलता को पहचानते हुए यह विजन डॉक्यूमेंट पूरे देश के नजरिए की जरूरत पर जोर देता है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा पक्की करने के लिए सैन्य ताकत को कूटनीतिक, तकनीकी और आर्थिक ताकत के साथ जोड़ा जाएगा। लगातार सुधारों, इनोवेशन और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के जरिए इसका मकसद यह पक्का करना है कि भारत की आजादी की सौवीं सालगिरह तक देश की सेना दुनिया भर में सम्मानित, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड और लड़ाई के लिए तैयार मिलिट्री के तौर पर खड़ी हो, जो मजबूत विकसित भारत में योगदान दे।

इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

तैयारी बढ़ने और देश की ग्रोथ में योगदान देने की उम्मीद है। विजन डॉक्यूमेंट में शॉर्ट-टर्म, मिड-टर्म और लॉन्ग-टर्म टाइमलाइन में साफ तौर पर प्राथमिकता वाले क्षमता लक्ष्यों के साथ एक कैलिब्रेटेड रोडमैप अपनाया गया है। यह विश्व स्तरीय डिफेंस फोर्स बनाने के लिए जरूरी सैन्य

निष्पक्ष और पारदर्शी कर प्रणाली समावेशी विकास की मजबूत नींव: राष्ट्रपति

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा है कि प्रत्यक्ष कर देश के विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक स्थिर राजस्व स्रोत के रूप में यह सरकारों को अवसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश करने में सक्षम बनाते हैं। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी कर प्रणाली समानता को बढ़ावा देती है और समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव तैयार करती है।

राष्ट्रपति भवन में मंगलवार को भारतीय राजस्व सेवा (आईटी) के 79वें बैच के अधिकारी प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि राजस्व सेवा का दायित्व केवल कर संग्रह तक सीमित नहीं है। जटिल वित्तीय लेन-देन का विश्लेषण करने, सीमाओं के पार अवैध वित्तीय प्रवाह का पता लगाने और जटिल कॉरपोरेट संरचनाओं को समझने की क्षमता आईआरएस अधिकारियों को विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में राष्ट्र का महत्वपूर्ण सहयोगी बनाती है। उन्होंने कहा कि युवा अधिकारियों से अपेक्षा है कि वे अपने आचरण और निर्णयों में विवेक बरतें।

एक विवेकपूर्ण अधिकारी प्रवर्तन और सुविधा, अधिकार और विनम्रता तथा तकनीकी क्षमता और मानवीय संवेदनशीलता के बीच संतुलन स्थापित करता है। उन्होंने अधिकारियों को सलाह दी कि वे अपने अधिकार का प्रयोग विनम्रता, संयम और संवैधानिक मूल्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ करें। भारतीय राजस्व सेवा (आईटी) के अधिकारी प्रशिक्षु वर्तमान में राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी, नागपुर में प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस बैच में भूटान की रॉयल भूटान सेवा के दो अधिकारी प्रशिक्षु भी शामिल हैं।

बिना किताबों के ही सीबीएसई स्कूलों में कैसे पढ़ेंगे बच्चे : जयराम ठाकुर

शिमला। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश में सीबीएसई में परिवर्तित किए गए स्कूलों की तैयारियों पर सवाल उठाते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर कड़ा प्रहार किया है। मंगलवार को शिमला से जारी बयान में उन्होंने कहा कि सरकार ने दो वर्ष पहले कई स्कूलों को सीबीएसई में परिवर्तित करने की घोषणा की थी, लेकिन पर्याप्त समय मिलने के बावजूद अभी तक आवश्यक व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं।

उन्होंने कहा कि कुछ स्कूलों में सीबीएसई के तहत पढ़ाई शुरू कर दी गई है, लेकिन एक महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं। ऐसे में बच्चों को बिना किताबों के ही पढ़ाई करनी पड़ रही है। उन्होंने बताया कि मार्च के अंत तक विद्यार्थियों का फॉर्मेटिव असेसमेंट होना है, जबकि अभी तक सीबीएसई की किताबें नहीं पहुंची हैं और स्कूलों में हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों से पढ़ाई करवाई जा रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार द्वारा यह तर्क देना कि सीबीएसई और हिमाचल बोर्ड का पाठ्यक्रम लगभग समान है, बेहद बचकाना है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों को ऐसे बयान देने के बजाय छात्रों को समय पर किताबें उपलब्ध कराने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अभी तक शिक्षकों के तबादले नहीं हुए हैं और वही शिक्षक पढ़ा रहे हैं जो पहले हिमाचल बोर्ड के तहत पढ़ाते थे। नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि सीबीएसई स्कूलों के लिए शिक्षकों की परीक्षा 22 मार्च को निर्धारित की गई है, ऐसे में चयन प्रक्रिया पूरी होने में अभी काफी समय लगेगा।

उन्होंने कहा कि बिना शिक्षक और पाठ्यपुस्तकों के सीबीएसई प्रणाली लागू करना छात्रों के हित में नहीं है। इससे पहले जयराम ठाकुर ने शिमला स्थित लोक भवन में नवनियुक्त राज्यपाल कविंद्र गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेकर उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं भी दीं। उन्होंने आशा जताई कि राज्यपाल अपने अनुभव से प्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

मनरेगा कर्मियों ने दी 12 से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी

पलामू। मनरेगा कर्मचारी संघ के आह्वान पर मांगों को लेकर राज्य के मनरेगा कर्मी 09 मार्च से 11 मार्च तक तीन दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर हैं। हड़ताल के दूसरे दिन मंगलवार को जिले के मनरेगा कर्मियों ने मेदिनीनगर के शिवाजी मैदान में बैठक कर अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। बैठक में जिले के विभिन्न प्रखंडों से बड़ी संख्या में पहुंचे मनरेगा कर्मियों ने हिस्सा लिया और एकजुटता के साथ आंदोलन को सफल बनाने का संकल्प लिया। बैठक में संघ के प्रदेश संयोजक देवेन्द्र उपाध्याय ने कहा कि राज्य के मनरेगा कर्मी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार अब तक उनकी समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर नहीं दिख रही है। कर्मियों ने कहा कि उन्हें कई महीनों से मानदेय नहीं मिल रहा है। इसके कारण उनके परिवार के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। मनरेगा योजना को धरातल पर लागू करने में कर्मियों की अहम भूमिका है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें स्थायी सेवा का दर्जा, सामाजिक सुरक्षा और समरूप वेतन जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। देवेन्द्र उपाध्याय ने कहा कि मनरेगा कर्मी पिछले कई वर्षों से नियमितीकरण, सामाजिक सुरक्षा और समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को लगातार अनदेखा कर रही है, जिससे कर्मियों में भारी असंतोष है। विकास पाण्डेय ने कहा कि मनरेगा देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है और इसे सफल बनाने में मनरेगा कर्मियों ने पिछले 18 वर्षों से पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य किया है। यह तीन दिवसीय सांकेतिक हड़ताल सरकार के लिए एक तरह का अल्टीमेटम है।

एलपीजी की कमी से बेंगलुरु का होटल उद्योग संकट में, केंद्र से तत्काल आपूर्ति बहाल करने की मांग

बेंगलुरु। पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर अब देश के होटल उद्योग पर भी दिखने लगा है। ईरान और इजराइल-अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष के कारण वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति प्रभावित होने से बेंगलुरु के होटल कारोबारियों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। शहर के कई होटल गैस की कमी के कारण बंद होने की स्थिति में पहुंच गए हैं। होटल संचालकों का कहना है कि एलपीजी की कमी के चलते कॉफी, चाय, नाश्ता और भोजन जैसी सेवाएं प्रभावित होने की आशंका है।

होटल व्यवसाय पूरी तरह वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों पर निर्भर करता है और इसके बिना होटल संचालन करना संभव नहीं है। ऐसे में गैस आपूर्ति बाधित होने से होटल उद्योग की गतिविधियां ठप पड़ने का खतरा बढ़ गया है। बेंगलुरु होटल मालिक संघ के अध्यक्ष पी.सी. राव ने मंगलवार को कहा कि गैस की कमी के कारण होटल उद्योग गंभीर संकट से गुजर रहा है। उन्होंने बताया कि कई होटल संचालकों को पर्याप्त एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे होटल संचालन में भारी दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि, केंद्र सरकार ने पहले यह दावा किया था कि देश में 60 से 70 दिनों तक का एलपीजी भंडार उपलब्ध है, लेकिन इसके बावजूद वाणिज्यिक गैस की आपूर्ति में आई बाधा ने होटल कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है। होटल एसोसिएशन ने राज्य सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने और जल्द समाधान निकालने की मांग की है।

होटल संचालकों ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से भी आग्रह किया है कि वे केंद्र सरकार से बातचीत कर वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति जल्द बहाल कराने के लिए दबाव बनाएं, ताकि होटल उद्योग को राहत मिल सके। इस मुद्दे को लेकर बेंगलुरु दक्षिण से सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी पहल की है। उन्होंने शहर के होटलों में एलपीजी सिलेंडरों की कमी को गंभीर बताते हुए इस मामले को केंद्र सरकार के संज्ञान में लाया है। सांसद ने केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर समस्या से अवगत कराया है।

अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि होटल और रेस्टोरेंट उद्योग अपने दैनिक भोजन पकाने के लिए मुख्य रूप से वाणिज्यिक एलपीजी पर निर्भर है, इसलिए इस क्षेत्र के लिए गैस की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। तेजस्वी सूर्या ने सरकार से इस समस्या के समाधान के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने की मांग की है।

उन्होंने इस संबंध में सोशल मीडिया के माध्यम से भी जानकारी साझा करते हुए कहा कि बेंगलुरु के होटल उद्योग को राहत दिलाने के लिए केंद्र से जल्द कार्रवाई की उम्मीद है।

विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रहा: रिजिजू

नई दिल्ली। लोकसभा में मंगलवार को अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए तीखा पलटवार किया। उन्होंने स्पीकर की निष्पक्षता तथा उनके कार्यकाल में संसद की कार्यक्षमता की प्रशंसा की।

अविश्वास प्रस्ताव को उन्होंने महज एक व्यक्ति की जिद करार देते हुए कहा कि विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रहा है। बहस की शुरुआत में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे सदन की कार्यवाही को पक्षपातपूर्ण तरीके से संचालित कर रहे हैं।

उन्होंने विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने का मौका न दिए जाने का जिक्र किया। गोगोई ने एक पुरानी घटना का हवाला दिया, जिसमें स्पीकर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने से रोका था, यह दावा करते हुए कि कुछ महिला सांसद प्रधानमंत्री की कुर्सी को घेरकर अप्रत्याशित स्थिति पैदा करने

की योजना बना रही थीं। गोगोई ने इसे शर्मनाक करार दिया और कहा कि स्पीकर का यह फैसला सदन की गरिमा के खिलाफ है। इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से सवाल किया कि क्या वे लोकसभा प्रोटोकॉल से ऊपर हैं? सदन में सभी सदस्य समान हैं और बोलने के लिए अध्यक्ष की अनुमति अनिवार्य है।

रिजिजू ने राहुल गांधी के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि सदन में बोलने के लिए किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। रिजिजू ने इसे असंसदीय बताते हुए कहा कि मंत्री होने से माइक्रोफोन खुद-ब-खुद ऑन नहीं हो जाता। स्पीकर का निर्णय अंतिम होता है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 122 का हवाला दिया, जिसके तहत स्पीकर के निर्णय को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, सिवाय अनुसूची 10 के तहत सदस्यता रद्द करने के मामलों के। रिजिजू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पीकर के फैसलों को अंतिम माना है।

इसके बाद रिजिजू ने गौरव गोगोई पर भी निशाना साधते हुए कहा कि गोगोई को संसदीय कार्य मंत्रालय के कामकाज की जानकारी नहीं है क्योंकि कांग्रेस पार्टी लंबे समय से सत्ता से बाहर रही है।

धौलपुर के पासपोर्ट आफिस को बम से उडाने की धमकी

धौलपुर। जिला मुख्यालय पर मुख्य डाकघर में स्थित पासपोर्ट आफिस को बम से उडाने की धमकी मिली है। मंगलवार दोपहर मेल पर आए धमकी के मैसेज के बाद में मुख्य डाकघर, पासपोर्ट आफिस तथा आसपास के इलाके को खाली कराया गया। पुलिस तथा अन्य एजेन्सी सतर्कता बरतते हुए पूरे मामले की पडताल में जुटीं हैं।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि दक्षिण भारत के कोयंबटूर से प्रदेश के जयपुर स्थित रीजनल पासपोर्ट कार्यालय को मेल भेजा गया। इस मेल में धौलपुर के मुख्य डाकघर स्थित पासपोर्ट कार्यालय को बम से उडाने की धमकी दी गई। मेल में धौलपुर के साथ ही प्रदेश के कई पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट ऑफिसों को दोपहर करीब एक बजे बम से उड़ाने की बात कही गई थी। जयपुर के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से मेल मिलने के बाद में धौलपुर के मुख्य डाकघर प्रशासन की ओर से पुलिस को बम की धमकी के संबंध में सूचित किया। सूचना मिलते ही थाना कोतवाली,थाना निहालगंज और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र से बाल विवाह के खिलाफ वैश्विक दिवस घोषित करने की मांग की

नई दिल्ली। दुनिया भर में हो रहे बाल विवाह की समस्या पर गंभीर चिंता जताते हुए भारत के बाल अधिकार कार्यकर्ता एवं विधिवेत्ता भुवन ऋभु ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र से बाल विवाह के उन्मूलन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित करने की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र के कमीशन ऑन द स्टैटस ऑफ वुमेन (सीएसडब्ल्यू) के 70वें सत्र के मौके पर एक कार्यक्रम में उन्होंने वर्चुअली माध्यम से कहा कि हाल के वर्षों में भारत में बाल विवाह में उल्लेखनीय कमी आई है लेकिन आज भी दुनिया में हर 3 सेकेंड में कहीं न कहीं एक बाल विवाह हो रहा है।

जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन के संस्थापक भुवन ऋभु ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को 'बाल विवाह उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस' की घोषणा करनी चाहिए ताकि इसके खिलाफ वैश्विक प्रतिबद्धता व जवाबदेही मजबूत हो और दुनिया भर की सरकारें तथा समाज इस अपराध को समाप्त करने के लिए संगठित हों। उन्होंने कहा कि भारत ने दिखाया है कि बाल विवाह का अंत संभव है। रोकथाम संरक्षण अभियोजन एवं बच्चों, समुदायों और धर्मगुरुओं की भागीदारी पर आधारित 'संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज' के दृष्टिकोण के साथ हमारा देश 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत में तीन वर्षों से भी कम समय में बाल विवाह की दर 23 प्रतिशत से घटकर 15 प्रतिशत से नीचे आ गई है। बाल विवाह दरअसल एक बच्चे के साथ होने वाले दुष्कर्म और यौन शोषण से कम नहीं है जिसे अक्सर संस्कृति या परंपरा की ओट में छिपा दिया जाता है। विशेषज्ञों ने यह भी रेखांकित किया कि कई देशों में बाल विवाह के खिलाफ सख्त कानूनी ढांचे पहले से मौजूद हैं लेकिन उनके कमजोर क्रियान्वयन के कारण यह प्रथा अब भी जारी है।

कार्यक्रम में मौजूद सिएरा लियोन की प्रथम महिला डॉ. फातिमा मादा बायो, नेपाल की महिला बाल एवं वरिष्ठ नागरिक मंत्री श्रद्धा श्रेष्ठ एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों ने बाल विवाह के खात्मे के लिए एक समर्पित अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित करने की मांग का पुरजोर समर्थन किया। इससे बाल विवाह के खिलाफ वैश्विक स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन और जवाबदेही को मजबूती मिलेगी। भुवन ऋभु वर्ल्ड लॉ कांग्रेस 2025 में वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन की ओर से 'मेडल ऑफ ऑनर' से सम्मानित हो चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने मधेपुरा जिले को दी 302 करोड़ रुपये की योजनाओं की सौगात, 158 योजनाओं का उद्घाटन एवं 137 का किया शिलान्यास

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज समृद्धि यात्रा के क्रम में मधेपुरा जिले में विभिन्न योजनाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी ली और कार्य तेजी से पूर्ण करने का निर्देश दिया।

इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने मधेपुरा पुलिस लाइन के प्रशासनिक एवं आवासीय भवनों का फीता काटकर उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम स्थल से रिमोट के माध्यम से शिलापट्ट अनावरण कर मधेपुरा जिले के लिए 86 करोड़ रुपये की लागत से 137 योजनाओं का शिलान्यास एवं 216 करोड़ रुपये की लागत से 158 योजनाओं का उद्घाटन किया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने इसी परिसर में लगाए गए विभिन्न विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जीविका दीदियों द्वारा क्रियान्वित विभिन्न कार्यों एवं उत्पादों की

जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि आप लोग इसी तरह से काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जीविका दीदियों ने भी मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि हम सब आपकी बदौलत ही आगे बढ़ रहे हैं।

हम सब जीविका दीदियां इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं। मुख्यमंत्री ने जीविका द्वारा संपोषित 15 हजार 748 स्वयं सहायता समूह की जीविका दीदियों को 176 करोड़ रुपये की राशि का सांकेतिक चेक प्रदान किया। उन्होंने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभुकों को चाबी प्रदान किया। साथ ही मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना के 60 लाभुकों को 8 लाख 70 हजार रुपये का सांकेतिक चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने जिला दिव्यांग सशक्तीकरण योजना के तहत दिव्यांगजनों को बैट्री चालित ट्राई साइकिल की चाबी प्रदान की। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम के तहत प्रत्येक को 4 लाख 12 हजार रुपये का अनुदान दान प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड के लाभार्थियों को भी आयुष्मान कार्ड प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और उत्पादों/कार्यों को देखा। मुख्यमंत्री ने स्टॉल निरीक्षण के दौरान जिले में कराए जा रहे विभिन्न विकासात्मक कार्यों के बारे में भी अधिकारियों से जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री सह जिले की प्रभारी मंत्री लेशी सिंह, विधान पार्षद ललन सर्राफ सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, पुलिस महानिदेशक विनय कुमार, सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ० बी० राजेन्दर, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, कोसी प्रमंडल के आयुक्त राजेश कुमार, कोसी प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक कुमार आशीष, मधेपुरा के जिलाधिकारी अभिषेक रंजन, पुलिस अधीक्षक डॉ० संदीप सिंह सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

उप्र कैबिनेट : प्रदेश के हर गांव में पहुंचेगी परिवहन की बसें

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 समेत 30 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। बैठक के बाद वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, राजस्व मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी दी।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के सभी 59 हजार ग्राम सभाओं तक बस पहुंचाने का निर्णय लिया है। मंगलवार को लोकभवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब प्रदेश के हर ग्रामसभा से बस होकर गुजरेगी। मौजूदा समय में लगभग 12 हजार ग्रामसभाओं में बसें नहीं जा पा रही हैं। उन गांवों तक बस पहुंचाने का निर्णय लिया गया है। उप्र परिवहन निगम के पास तीन हजार बसें हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी बसें चलाई जाएंगी और बसें 28 सीटर होंगी। निजी क्षेत्र की बसों को अनुबंधित कर चलाया जाएगा। किराया का निर्धारण जिला अधिकारी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय गठित कमेटी वहां की परिस्थिति को देखते हुए करेगी। जिलावार गठित कमेटी अपने-अपने जिलों के लिए बसों का अनुबंध करेगी। बसों के संचालन का समय निर्धारण जनता की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। ताकि गांव के लोग समय से जिला मुख्यालय पहुंच सकें। अपना काम पूरा कर वापस सयम से गांव आ जाएं। दयाशंकर सिंह ने बताया कि अब ओला, ऊबर जैसी कम्पनियों को उप्र परिवहन निगम में पंजीकरण कराना होगा। हर पांच साल में उन्हें पांच हजार रुपये शुल्क देकर पंजीकरण रिन्यू कराना होगा। इससे प्रदेश की सड़कों पर चलने वाले ऐसे वाहनों के बारे में पूरी जानकारी होगी। परिवहन निगम एक ऐप भी बनाएगा। उसमें ओला, ऊबर की गाड़ियों और उसके चालक की पूरी जानकारी होगी। ओला ऊबर को भी एक ऐप बनाना होगा। यह ऐप आम जन के लिए उपलब्ध होगा। उन्होंने बताया कि यूपीएसआरटीसी की ऐसी कोई बस नहीं है जिसमें जीपीएस सिस्टम नहीं लगा हो। सभी बसों की पूरी निगरानी की जा रही है। स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

अब प्रापर्टी बेचने वाले की पहचान को खतौनी में देखा जाएगा। स्टाम्प निबंधन विभाग अब मालिकाना हक को चेक करेगा। बिना मालिकियत को जांच किए अब स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। विभाग के मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने बताया कि सर्किल रेट के आधार पर ही स्टाम्प शुल्क लगेगा। नगर निगम सीमा के अंदर दो प्रतिशत विकास शुल्क अलग से देय होगा।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 13 मार्च को ग्रीन कॉरिडोर का करेंगे शुभारंभ

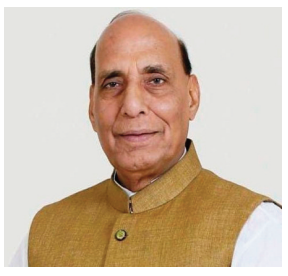

लखनऊ। लखनऊ से सांसद एवं केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 व 13 मार्च को अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने बताया कि रक्षा मंत्री 12 मार्च को रात्रि लगभग 8:00 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे।

एयरपोर्ट से प्रस्थान करके रात्रि 8:30 बजे पारिवारिक वैवाहिक समारोह में सम्मिलित होंगे। इसके उपरांत रात्रि विश्राम 5-ए, कालिदास मार्ग पर करेंगे। रक्षा मंत्री 13 मार्च शुक्रवार को प्रातः 11:20 बजे कालिदास मार्ग स्थित आवास से प्रस्थान कर 11:30 बजे सी.एम.एस. गोल्फ सिटी, सेक्टर-सी, पॉकेट-9 पहुंचेंगे, जहां वह सिटी मोंटेसरी स्कूल की गोल्फ सिटी शाखा के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेंगे। रक्षा मंत्री इसके बाद राजाजीपुरम में विधायक योगेश शुक्ला के आवास तथा राजेंद्र नगर स्थित विधायक निवास में स्वर्गीय विंध्यवासिनी कुमार (पूर्व एमएलसी) के आवास जाएंगे। रक्षा मंत्री शाम लगभग 4:30 बजे समतामूलक चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे तथा समतामूलक चौराहे से डालीगंज पुल तक ग्रीन कॉरिडोर का अवलोकन करेंगे और कर्मचारियों को सम्मानित करेंगे।

सायं 5:00 बजे झूलेलाल वाटिका, हसनगंज में आयोजित जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के उपरांत रक्षा मंत्री सायं लगभग 6:20 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे।

रक्तदान करने वाले 19 लोगों में 'हेपेटाइटिस बी' संक्रमण की पुष्टि

लखनऊ। 24 फरवरी को आयोजित एक रक्तदान शिविर में रक्तदान करने वाले लगभग 19 लोगों में हेपेटाइटिस बी संक्रमण की पुष्टि हुई है। लखनऊ के सीएमओ डॉ. एनबी सिंह ने मंगलवार को बताया कि पहली जांच के नतीजों की पुष्टि के लिए रविवार को एक शिविर आयोजित किया गया था। रिपोर्टों की दोबारा जांच की जा रही है। जिन 19 लोगों में जांच में संक्रमण पाया गया था, उन सभी के दूसरे नमूने रविवार को लिए गए। उन्होंने बताया कि रक्तदान शिविर 24 फरवरी को लखनऊ के मलिहाबाद ब्लॉक के मुंशी खेड़ा और तीन अन्य गांवों में आयोजित किया गया था। सीएमओ ने बताया कि शिविर की तुलना में अधिक नमूने लिए गए और नमूनों को जांच के लिए केजीएमयू भेजा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, हेपेटाइटिस बी एक वायरल संक्रमण है जो लीवर पर हमला करता है और गंभीर व दीर्घकालिक दोनों प्रकार की बीमारी का कारण बन सकता है। यह वायरस सबसे आम तौर पर जन्म और प्रसव के दौरान मां से बच्चे में फैलता है, साथ ही साथ संक्रमित साथी के साथ यौन संबंध के दौरान रक्त या अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में आने, असुरक्षित इंजेक्शन या नुकीले उपकरणों के संपर्क में आने से भी फैलता है।

संक्षिप्त खबरें

पालतू पिल्ले को पीट-पीटकर मार डाला, 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

शाहजहांपुर। जिले में एक पालतू पिल्ले के कब्रिस्तान में घुसने पर उसे कथित रूप से पीट-पीटकर मार देने के मामले में पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजेश द्विवेदी ने बताया कि थाना सदर बाजार क्षेत्र के लाल तेली बजरिया निवासी करन का पालतू पिल्ला कब्रिस्तान में चला गया था और वहां मौजूद पांच लोगों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। पड़ोस की छत पर जाकर करन ने इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। द्विवेदी ने बताया कि पिल्ला बचने के लिए चारपाई के नीचे छिप गया, लेकिन आरोपी उसे वहां से खींचकर फिर पीटते रहे, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने बताया कि इसके बाद आरोपी पिल्ले को बोरी में डालकर ले गए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना सात मार्च की है, लेकिन पुलिस में शिकायत सोमवार को जीव सहयोग फाउंडेशन के एक अधिकारी ने दर्ज कराई।

एटा में आंगनबाड़ी केंद्रों से पैसा वसूली का निर्देश देने के आरोप में सीडीओ निलंबित

एटा। एटा के मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वह जिला समन्वयक से हर आंगनबाड़ी केंद्र से 10 हजार रुपये की व्यवस्था कराने की बात कहते हुए दिख रहे हैं। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वीडियो सामने आने के बाद सीडीओ नागेंद्र नारायण मिश्रा को निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि वीडियो में जिला समन्वयक संजीव पचौरी के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों से धनराशि जुटाने को लेकर चर्चा हो रही है। सूत्रों के अनुसार, जिला समन्वयक ने इस मांग को मानने से कथित तौर पर इनकार कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन तक इस मामले की जानकारी पहुंची। जिलाधिकारी कार्यालय से जब इस संबंध में प्रतिक्रिया मांगी गई तो अधिकारियों ने कहा कि वायरल वीडियो के संबंध में वही व्यक्ति अधिक जानकारी दे सकता है जिसने इसे सोशल मीडिया पर डाला है। इस मामले पर मौर्य ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, "एटा के मुख्य विकास अधिकारी नागेंद्र नारायण मिश्रा द्वारा कथित रूप से रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल होने के मामले में उनके विरुद्ध नियम के तहत विभागीय कार्यवाही शुरु की गई है और उन्हें निलंबित कर दिया गया है।" वहीं मिश्रा ने वायरल वीडियो को भ्रामक बताते हुए कहा कि वीडियो में तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। मिश्रा ने कहा कि उन्होंने किसी से भी किसी प्रकार की धनराशि नहीं मांगी।

दहेज उत्पीड़न से तंग आकर महिला ने की आत्महत्या, सास-ससुर गिरफ्तार

बलिया। जिले की पुलिस ने दहेज उत्पीड़न से तंग आकर एक महिला के कथित रूप से खुदकुशी करने के मामले में उसके सास-ससुर को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि महिला के पति के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस के अनुसार, रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के सरदासपुर गांव निवासी श्रीनाथ की तहरीर पर बनिया बांध गांव के निवासी कमलेश कुशवाहा, उसके पिता पारस कुशवाहा और मां किरण के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। श्रीनाथ ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उनकी बेटी राधिका का विवाह अप्रैल 2025 में कमलेश से हुआ था और दहेज को लेकर ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ित किए जाने से तंग आकर उनकी बेटी ने आठ मार्च को फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि इस मामले में भारतीय न्याय संहिता और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। रसड़ा क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक आलोक गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने मंगलवार को आरोपी पारस कुशवाहा और किरण को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि फरार आरोपी कमलेश कुशवाहा की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

नाबालिग से कुकर्म करने के आरोप में साधु गिरफ्तार

मथुरा। नाबालिग लड़के से कुकर्म करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। जैंत थाने के प्रभारी उमेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि बाटी गांव के निकट कुटिया बनाकर रहने वाले साधु कमलकृष्ण ने आठ मार्च को 14 वर्षीय लड़के को अपने पास बुलाया और कुकर्म किया। त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी ने बच्चे को धमकाते हुए कहा कि अगर उसने किसी को भी इसकी जानकारी दी, तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद डर की वजह से बच्चे ने अपने माता-पिता को घटना की जानकारी नहीं दी लेकिन सोमवार को एक वीडियो वायरल होने के बाद गांव वालों को आरोपी की हरकत का पता चला। त्रिपाठी ने बताया कि बच्चे के पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और थाने ले जाते समय गुस्साए गांववालों ने उसकी पिटाई कर दी। उन्होंने बताया कि तहरीर के आधार पर मामला दर्ज करके बच्चे को जांच के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है तथा आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

दो मोटरसाइकिल खड़े ट्रक से टकराईं, तीन लोगों की मौत

अमेठी। जिले में दो मोटरसाइकिल के सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराने के कारण पिता-पुत्री समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार यह घटना सोमवार देर शाम फुरसतगंज थाना क्षेत्र में रायबरेली-सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर निगोहां गांव के पास उस वक्त की है जब दो मोटरसाइकिल पर सवार सात लोग रायबरेली की ओर जा रहे थे। उसने बताया कि सामने से आ रहे तेज रफ्तार वाहन से बचने के प्रयास में दोनों मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गईं।

पुलिस ने बताया कि हादसे में सभी सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुरसतगंज ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जायस निवासी अतुल (38) व उनकी बेटी दिशा (छह) और हीरालाल (45) को मृत घोषित कर दिया। उसने बताया कि घायल रानी (30), शिवानी (18) और पल्लवी (16) को गंभीर हालत में रायबरेली के जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जबकि माही (12) का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुरसतगंज में किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि सभी आपस में रिश्तेदार बताए गए हैं और ये सभी जायस के एक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद घर लौट रहे थे। पुलिस क्षेत्राधिकारी (तिलोई) दिनेश कुमार मिश्रा ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं और ट्रक को पुलिस ने जब्त कर लिया है।

पेड़ से टकराई बाइक, दो युवकों की मौत

कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर रेउना थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक नीलगाय से बचने के प्रयास में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। हादसे में बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे को गंभीर हालत में हैलट अस्पताल रेफर किया गया। वहां उपचार के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। कानपुर देहात निवासी (26) कैलाश पाल अपने साथी (28) छोटू पाल के साथ देर रात बाइक से किसी निजी काम से घाटमपुर की ओर जा रहे थे। जैसे ही दोनों रेउना थाना क्षेत्र के दरौली गांव के पास पहुंचे, तभी अचानक बाइक के सामने नीलगाय आ गई। नीलगाय को बचाने के प्रयास में बाइक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खड़े पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और दोनों युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क किनारे गिर पड़े। हादसा देख आसपास से गुजर रहे राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को घटना की जानकारी देते हुए दोनों घायलों को घाटमपुर सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने कैलाश पाल को मृत घोषित कर दिया। वहीं छोटू पाल की हालत गंभीर देखते हुए उसे हैलट अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। रेउना थाना प्रभारी अनुज राजपूत ने बताया कि हादसे में दोनों युवकों की मौत हुई है। मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

सड़क दुर्घटना में कार सवार दो युवकों की मौत

देवरिया। जिले में एक कार के अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से दो युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार यह घटना सोमवार देर रात बरियारपुर थाना क्षेत्र के महुआनी-सोनू घाट मार्ग पर उस वक्त हुई जब टोला जेठहंसी के निवासी अतुल पांडेय उर्फ प्रिंस पांडेय (28) और खुखुंदू निवासी आकाश पाल (19) एक बारात में शामिल होकर लौट रहे थे तभी उनकी क्रेटा कार अचानक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उसने बताया कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। बरियारपुर थाना प्रभारी दीपक सिंह ने बताया कि अतुल पांडेय बैकुंठपुर में कपड़ों का कारोबार करता था जबकि आकाश पाल उसकी दुकान में कर्मचारी के रूप में काम करता था। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

गैंगस्टर आरोपित राइस मिल मालिक की 15 करोड़ रुपये की जमीन कुर्क

मीरजापुर। जनपद के राजगढ़ थाना क्षेत्र के ददरा गांव निवासी गैंगस्टर एक्ट के आरोपित राइस मिल मालिक शैलेश कुमार सिंह की करीब 10 बीघा जमीन को मंगलवार को प्रशासन ने कुर्क कर लिया। न्यायालय जिलाधिकारी के आदेश पर हुई इस कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल और राजस्व विभाग की टीम मौके पर मौजूद रही।

थाना प्रभारी निरीक्षक वेद प्रकाश पांडेय ने बताया कि ददरा गांव निवासी धान व्यवसायी शैलेश कुमार सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट, अपहरण, मारपीट व एससी/एसटी एक्ट सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपित द्वारा अर्जित संपत्तियों के संबंध में पुलिस ने रिपोर्ट जिलाधिकारी न्यायालय को भेजी थी। मामले को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी न्यायालय ने आरोपित शैलेश कुमार सिंह की अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया। आदेश के अनुपालन में मंगलवार को उपजिलाधिकारी मड़िहान अनेग सिंह के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम और पुलिस बल मौके पर पहुंचा। कार्रवाई के दौरान राजगढ़ थाना प्रभारी वेद प्रकाश पांडेय, संतनगर थाना प्रभारी राजेश कुमार, मड़िहान प्रभारी बालमुकुंद मिश्र व अहरौरा थाना की पुलिस फोर्स मौजूद रही।

प्रशासन ने माइक और लाउडस्पीकर से मुनादी कराकर ददरा ग्राम पंचायत में दो बीघा तथा राजगढ़ ग्राम सभा में स्थित आठ बीघा जमीन को कुर्क कर सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। इसके बाद जमीन पर पुलिस की ओर से कुर्की का बैनर भी लगा दिया गया। राजस्व विभाग के अनुसार कुर्क की गई जमीन की अनुमानित कीमत लगभग 15 करोड़ रुपये आंकी गई है।

राज्य महिला आयोग की सदस्य ने किया महिला शिकायतों का त्वरित निस्तारण

वाराणसी। जिले में सर्किट हाउस में राज्य महिला आयोग की सदस्य गीता विश्वकर्मा ने मंगलवार को जनसुनवाई कर महिलाओं से जुड़े मामलों का त्वरित निस्तारण किया। इस दौरान कुछ प्रकरण में विधि प्राधिकरण के अधिकारियों की भूमिका को देखते हुए उन्हें सौंप दिया गया। राज्य महिला आयोग की सदस्य गीता विश्वकर्मा ने कहा कि आयोग महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा के लिए निरंतर सुनवाई करा रहा है। आयोग की सुनवाई के दौरान पीड़ित महसूस कर रही महिलाएं अपना विषय बिंदु रख सकती हैं। जिस भी विभाग के अधिकारी महिला प्रकरण को गंभीरता से नहीं ले रहे है, उस शिकायत को आयोग तक पहुंचा सकती है। राज्य महिला आयोग प्रत्येक मामले में दोनों पक्षों को सुनता है और तथ्य के आधार पर कार्रवाई करता है। आज सुनवाई के दौरान उनके सामने 77 प्रकरण आए थे। जिसमें 41 प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है, जबकि 33 मामले अभी आयोग के समक्ष लंबित हैं।

5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के आरोप में रालोद के विधान परिषद सदस्य के खिलाफ मामला दर्ज

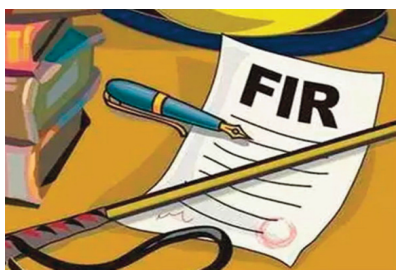

मथुरा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में धोखाधड़ी से फर्जी दस्तावेज बनवाकर करोड़ों रुपये की जमीन कब्जाने के प्रयास, पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और धमकी देने के आरोप में एक अदालत के आदेश पर राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) योगेश नौहवार समेत पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

हाईवे थाना में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार कलाकुंज कॉलोनी की निवासी निधि अग्रवाल ने कहा है कि वह रामहरी एंटरप्राइजेज नामक कंपनी में साझीदार हैं और वह और उनके पति जमीन कारोबार करते हैं। शिकायत में बताया गया है कि उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट पांच एकड़ जमीन का सौदा करके जून 2024 में जमीन की रजिस्ट्री कराई थी और बाद में उस जमीन की बिक्री करके दाखिल-खारिज भी करा लिया था। उनका आरोप है कि इसके बाद नौहवार समेत पांच लोगों ने उन्हें अपने यहां बुलाकर उक्त जमीन अपनी बताते हुए मामला निपटाने के लिए पांच करोड़ रुपये की मांग की और पैसे न देने पर धमकाने की कोशिश की।

शिकायत में कहा गया है कि इसके लिए उन्होंने धोखाधड़ी के जरिये जाली दस्तावेज बनवाकर उक्त जमीन पर अपना दावा जताया। हाईवे थाने के प्रभारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय (संख्या-2) के आदेश पर आठ मार्च को नौहवार, यश चौधरी, मनीष अदलक्खा, शुभम अग्रवाल व कृष्ण मुरारी अग्रवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और जांच उपनिरीक्षक रोहन कुचलिया को सौंपी गई है।

दूसरी ओर नौहवार ने खुद पर लगे आरोपों को पुरी तरह बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि वह खुद शिकायतकर्ताओं के खिलाफ जमीन कब्जाने के प्रयास, जालसाजी एवं धोखाधड़ी से फर्जी कागजात बनवाने के आरोप में दो मामले दर्ज करा चुके हैं। उन्होंने कहा कि अदालत को पूरी जानकारी दिए बिना ये आदेश जारी कराए हैं।

छह लोग गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी करार 10-10 साल की सजा

बलिया। बलिया की एक स्थानीय न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या के 12 साल पुराने मामले में चार सगे भाई-बहन सहित छह लोगों को दोषी करार देते हुए दस-दस साल के कारावास की सजा सुनाई। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश राम कृपाल की अदालत ने सोमवार को सुनवाई के दौरान हरेन्द्र यादव, उसके भाई रवीन्द्र यादव, दो बहनें बबिता व सहती, उर्मिला देवी और विनोद यादव को दोषी करार देते 11-11 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा भी सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार, हल्दी थाना क्षेत्र के हल्दी पश्चिम टोला गांव में 14 मई 2014 को जमीन विवाद के दौरान आरोपियों ने गाली-गलौच करते हुए लाठी और डंडे से जयशंकर पर हमला किया। गंभीर रूप से घायल जयशंकर की इलाज के दौरान मौत हो गई। जयशंकर के भाई गौरीशंकर यादव की तहरीर पर हरेन्द्र यादव, रवीन्द्र यादव, बबिता, सहती, उर्मिला देवी और विनोद यादव के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच के बाद सभी छह आरोपियों के विरुद्ध अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया।

होली के बाद कानपुर में रंगों का ऐतिहासिक गंगा मेला शुरू, गलियों में रंग और उल्लास का दिख रहा नजारा

कानपुर। देश भर में होली का रंग भले ही उतरने लगा हो, लेकिन कानपुर में रंगों का असली उत्सव अब शुरू होता है। सदियों पुरानी परंपरा और अनोखी रंग-बिरंगी झलकियों के लिए प्रसिद्ध ऐतिहासिक गंगा मेले की शुरुआत मंगलवार को हटिया स्थित रज्जन बाबू पार्क में झंडारोहण के साथ हुई। जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने मंगलवार को ध्वजारोहण कर मेले का शुभारंभ किया, जिसके साथ ही शहर की गलियों में रंग और उल्लास का अनोखा नजारा दिखाई देने लगा।

गंगा मेले की पहचान रंगों से सजे ठेलों के साथ निकलने वाली टोलियों से होती है। ये टोलियां शहर की तंग गलियों और पुराने बाजारों से गुजरते हुए लोगों को अपने साथ इस रंगोत्सव में शामिल करती चलती हैं। ढोल-नगाड़ों की गूंज, उड़ता अबीर-गुलाल और रंगों से सराबोर लोग—यह दृश्य कानपुर की सांस्कृतिक पहचान बन चुका है। टोलियां आगे बढ़ते हुए बहाना रोड तक पहुंचेंगी, जहां मटकी फोड़ और कपड़ा फाड़ होली का आयोजन किया जाएगा, जिसे देखने के लिए हर साल हजारों लोग उमड़ते हैं। कार्यक्रम में पुलिस उपायुक्त पूर्वी सत्यजीत गुप्ता, भाजपा एमएलसी सलील बिश्नोई, आर्यनगर विधायक अमिताभ बाजपेयी, हटिया मेला कमेटी के सदस्य तथा हास्य कलाकार अनु अवस्थी सहित कई जनप्रतिनिधि और इलाकाई लोग मौजूद रहे।

गंगा मेला कमेटी के अध्यक्ष ज्ञानेश बिश्नोई ने बताया कि इस वर्ष 85वां गंगा मेला आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी कारणवश इस बार भैंस ठेला गंगा मेले का हिस्सा नहीं बन पाया है। हालांकि टोलियों में ट्रैक्टर-गाड़ियां और ऊंट लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। दोपहर तक चलने वाले इस रंगोत्सव के बाद सरसैया घाट पर गंगा मेले का मुख्य आयोजन होगा, जहां बड़ी संख्या में लोग गंगा तट पर पहुंचकर एक-दूसरे को बधाई देंगे और इस ऐतिहासिक परंपरा का हिस्सा बनेंगे। दरअसल, गंगा मेले की परंपरा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के 43 क्रांतिकारियों जुड़ी मानी जाती है।

जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में जीत के बाद क्रांतिकारियों और शहरवासियों ने गंगा तट पर एकत्र होकर रंग खेलते हुए इस उत्सव को मनाया था। तभी से यह परंपरा आज तक चली आ रही है और हर वर्ष होली के बाद कानपुर में गंगा मेला बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है।

परीक्षा देने जा रहे सात छात्र सड़क हादसे में घायल, पुलिस ने पांच को दिलाई परीक्षा

औरैया। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के फफूंद क्षेत्र में मंगलवार को हाईस्कूल की परीक्षा देने जा रहे छात्रों के साथ सड़क हादसा हो गया। भाग्यनगर के पास दिबियापुर मार्ग पर एक ऑटो में पीछे से लगातार तीन बाइक टकरा गईं, जिससे सात छात्र घायल हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से सीएचसी दिबियापुर में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद पुलिस ने पांच छात्रों को उनके परीक्षा केंद्र किसान इंटर कॉलेज भाग्यनगर पहुंचाकर परीक्षा दिलवाई।

जानकारी के अनुसार भौनकपुर निवासी शैलेन्द्र, रोहित, शिवकांत और शिवा दो बाइक से परीक्षा देने जा रहे थे। जैसे ही वे भाग्यनगर के पास पहुंचे, एक बाइक आगे चल रहे ऑटो से टकरा गई। इसके बाद पीछे आ रही दूसरी बाइक भी भिड़ गई। इसी दौरान दयानगर निवासी शैलेन्द्र नायक, अमित नायक और राऊपुर निवासी विकास की बाइक भी पीछे से टकरा गई। हादसे में सात छात्र घायल हो गए। इनमें शैलेन्द्र नायक, रोहित, विकास, शैलेन्द्र और अभिषेक को प्राथमिक उपचार के बाद पुलिस की मदद से परीक्षा केंद्र पहुंचा दिया गया।

वहीं भौनकपुर निवासी शिवाकांत और शिवा की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जिससे वे परीक्षा देने से वंचित रह गए। इस संबंध में थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। पांच छात्रों को पुलिस स्टाफ के साथ परीक्षा दिलाने भेज दिया गया, जबकि दो गंभीर घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।

टी20 विश्व कप विजेता टीम को 131 करोड़ रुपये का पुरस्कार देगा BCCI

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने तीसरी बार पुरुष टी20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम और सहयोगी स्टाफ के सदस्यों के लिए मंगलवार को 131 करोड़ रुपये के पुरस्कार की घोषणा की।

यह पुरस्कार राशि 15 खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ और अन्य सहयोगी स्टाफ में वितरित की जाएगी। सूत्रों के अनुसार, सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम के खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि का बड़ा हिस्सा मिलना तय है, जबकि सहयोगी स्टाफ के सदस्यों के लिए पुरस्कार राशि उनके पद के अनुसार तय की जाएगी। यह राशि 2024 में रोहित शर्मा की अगुवाई वाली चैंपियन टीम को दिए गए 125 करोड़ रुपये से छह करोड़ रुपये अधिक है। सूत्रों के अनुसार15 खिलाड़ियों में से प्रत्येक को छह करोड़ रुपये मिलेंगे जबकि शेष 41 करोड़ रुपये सहयोगी स्टाफ के सदस्यों में वितरित किए जाएंगे।

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने बयान में कहा, ''बोर्ड इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर खिलाड़ियों, सहयोगी स्टाफ के सदस्यों और चयनकर्ताओं को एक बार फिर बधाई देता है और भविष्य में उनकी निरंतर सफलता की कामना करता है ।'' भारत ने रविवार को अहमदाबाद के नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर यह प्रतिष्ठित ट्रॉफी अपने नाम की थी। वह टी20 विश्व कप में खिताब का सफल बचाव करने वाली पहली टीम है। भारतीय टीम ने तीसरी बार यह टूर्नामेंट जीता।

यह कारनामा करने वाली वह पहली टीम बन गई जिससे खेल के इस छोटे प्रारूप में उसके दबदबे का भी पता चलता है।

प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट बनकर संजू सैमसन ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड

नई दिल्ली। भारत को तीसरी बार टी20 विश्व कप का खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन ने हाल में समाप्त हुई प्रतियोगिता का 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' बनकर एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर दिया। सैमसन पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने आईसीसी (अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) के पुरुष या महिला वर्ग के किसी टूर्नामेंट में अपनी टीम की तरफ से चार मैच नहीं खेलने के बावजूद 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' का पुरस्कार हासिल किया। उनसे पहले चार खिलाड़ी ही ऐसे थे जिन्होंने अपनी टीम के सभी मैच नहीं खेलने के बावजूद टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता था। इन खिलाड़ियों ने हालांकि अपनी टीम की तरफ से केवल एक मैच नहीं खेला था।

प्रतियोगिता के शुरू होने पर सैमसन रन बनाने के लिए जूझ रहे थे और इसलिए उन्हें शुरुआती मैचों में अंतिम एकादश में नहीं चुना गया था। उन्हें बीच में अभिषेक शर्मा के अस्वस्थ होने के कारण एक मैच खेलने का मौका मिला लेकिन उसके बाद उन्हें बाहर कर दिया गया था। सुपर आठ में दक्षिण अफ्रीका से बड़ी हार के बाद भारत ने अपने शीर्ष क्रम में बाएं हाथ के बल्लेबाजों की अधिकता को देखते हुए दाएं हाथ के बल्लेबाज सैमसन को मौका दिया और केरल के इस खिलाड़ी ने इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। सैमसन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ क्वार्टर फाइनल की तरह

बने मैच में नाबाद 97 रन बनाए। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 89 और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में भी 89 रन बनाकर भारत को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इसके लिए उन्हें टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। भारत ने इस टूर्नामेंट में कुल नौ मैच खेले जिनमें से सैमसन पांच मैच ही खेल पाए थे। आईसीसी के पुरुष या महिला वर्ग के टूर्नामेंट में इससे पहले 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' बनने वाले किसी खिलाड़ी ने या तो अपनी टीम के सभी मैच खेले थे या फिर वे केवल एक मैच से बाहर रहे थे।

मैथ्यू हेडन को गुजरात टाइटन्स ने बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया

अहमदाबाद। गुजरात टाइटन्स ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के आगामी सत्र से पहले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन को बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है। फ्रेंचाइजी ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। दो बार के वनडे विश्व कप विजेता और अपने जमाने के सबसे प्रभावशाली सलामी बल्लेबाजों में से एक हेडन का अंतरराष्ट्रीय करियर शानदार रहा है।

उन्हें टी20 में बल्लेबाजी का व्यापक अनुभव है और वह इसकी बारीकियों को समझते हैं। हेडन ने सभी प्रारूपों में 273 अंतरराष्ट्रीय मैचों में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें उन्होंने 15,000 से अधिक रन बनाए और आईसीसी के कई टूर्नामेंट में जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुजरात टाइटंस के क्रिकेट निदेशक विक्रम सोलंकी ने कहा, ''मैथ्यू की नियुक्ति हमारे सफर के महत्वपूर्ण मोड़ पर की गई है। शीर्ष स्तर पर उनका अनुभव और उभरती प्रतिभाओं को मार्गदर्शन देने की उनकी क्षमता आगामी सत्र में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।'' हेडन ने कहा, ''अच्छी बल्लेबाजी दबाव बनाती है। शानदार बल्लेबाजी खेल पर अपना दबदबा बनाती है। गुजरात टाइटन्स में हम यही मानक स्थापित करना चाहते हैं।'' हेडन ने बल्लेबाजी के प्रति अपने आक्रामक रवैये और तकनीकी रूप से मजबूत शैली से सीमित ओवरों की क्रिकेट में पावरप्ले में दबदबा बनाने की शुरुआत की थी।

वह आईपीएल में भी 32 मैच खेले हैं जिनमें उन्होंने अपनी आक्रामक अंदाज की बल्लेबाजी से विशेष छाप छोड़ी थी। यह पता चला है कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर मैथ्यू वेड के इस साल गुजरात टाइटंस के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा बनने की संभावना नहीं है।

विश्व कप फुटबॉल बहुत बड़ा टूर्नामेंट, स्थगित करना आसान नहीं: मुख्य संचालन अधिकारी

डलास। फीफा विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता के मुख्य संचालन अधिकारी हेइमो शिर्गी ने कहा कि यह बहुत बड़ा टूर्नामेंट है तथा अमेरिका और इजरायल के ईरान के खिलाफ युद्ध के कारण उत्पन्न वैश्विक उथल-पुथल के चलते इसे स्थगित करना आसान नहीं होगा। विश्व कप 11 जून से अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में खेला जाएगा जिसमें पहली बार 48 देश भाग लेंगे। इनमें ईरान भी शामिल है।

शिर्गी ने सोमवार को अंतरराष्ट्रीय प्रसारण केंद्र में कहा कि फीफा ईरान युद्ध और उसके नतीजों पर करीबी नजर रखे हुआ है। शिर्गी ने कहा कि अगर मैं भविष्यवक्ता होता मैं अभी बता सकता था कि क्या होने वाला है, लेकिन जाहिर है कि स्थिति बदल रही है। उन्होंने कहा कि हालात दिन-प्रतिदिन बदल रहे हैं और हम उन पर कड़ी नजर रख रहे हैं। हम अपने

सभी संघीय और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ मिलकर स्थिति का मूल्यांकन कर रहे हैं। हम हर दिन के हिसाब से चल रहे हैं और किसी न किसी स्तर पर हमें इसका समाधान मिल जाएगा।

विश्व कप तो होगा ही, है ना? विश्व कप बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और हम उम्मीद करते हैं कि क्वालीफाई कर चुके सभी देश इसमें भाग लेंगे। विश्व कप फुटबॉल में इससे पहले 32 देश भाग लेते थे लेकिन पहली बार इस टूर्नामेंट में 48 देश भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता का आयोजन अमेरिका के 11, मैक्सिको के तीन और कनाडा के दो स्थानों पर किया जाएगा।

अमेरिका ने पहले ही विश्व कप के लिए क्वालीफाई कर चुके चार देशों ईरान, आइवरी कोस्ट, हैती और सेनेगल पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन खिलाड़ियों, टीम अधिकारियों और उनके करीबी रिश्तेदारों को छूट देने की बात कही है। शिर्गी ने कहा कि फीफा नयी जानकारी हासिल करने के लिए ईरानी फुटबॉल महासंघ के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने हालांकि इन बातचीत का ब्यौरा नहीं दिया। फीफा के अधिकारी डलास में 'फैन फेस्टिवल' के कार्यक्रमों की घोषणा करने के लिए इस शहर में थे। यह कार्यक्रम विश्व कप के दौरान 34 दिन तक चलेगा।

ऑस्ट्रेलिया ने ईरानी महिला फुटबॉल टीम की पांच सदस्यों को शरण दी: अधिकारी

ब्रिसबेन। ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्री टोनी बर्क ने मंगलवार को कहा कि उनके देश ने टूर्नामेंट के लिए ईरान से आई महिला फुटबॉल टीम की पांच सदस्यों को शरण दी है। स्थानीय समयानुसार मंगलवार तड़के ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस के अधिकारियों ने इन ईरानी महिला खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट स्थित उनके होटल से ''एक सुरक्षित स्थान'' पर पहुंचाया। बर्क ने कुछ देर बाद ब्रिसबेन में पत्रकारों को बताया कि महिला खिलाड़ियों ने वहां उनसे मुलाकात की और मानवीय आधार पर उनके वीजा की प्रक्रिया पूरी हो गई। ईरान युद्ध शुरू होने से ठीक पहले पिछले महीने महिला एशियाई कप के लिए ईरानी टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी। सप्ताहांत में टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई जिसके बाद टीम को अपने देश लौटना था जहां युद्ध के कारण हालात खराब हैं।

वेस्टइंडीज दौरे के लिए ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम घोषित, सोफी मोलिन्यूक्स को कप्तानी

मेलबर्न। ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी व्हाइट-बॉल सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। टीम की कमान ऑलराउंडर सोफी मोलिन्यूक्स को सौंपी गई है, जबकि विकेटकीपर बल्लेबाज ताहलिया विल्सन को पहली बार टीम में जगह मिली है। टीम में लूसी हैमिल्टन और निकोला कैरी को भी बरकरार रखा गया है, जो हाल ही में भारत के खिलाफ खेली गई सीरीज का हिस्सा थीं। वहीं भारत के खिलाफ टी20 टीम में शामिल रहीं ग्रेस हैरिस को इस बार टीम में जगह नहीं मिली है।

इसके अलावा ऑलराउंडर एनेबेल सदरलैंड इस दौरे से बाहर रहेंगी। चयनकर्ताओं के अनुसार पिछले 12 महीनों में अधिक क्रिकेट खेलने के कारण उनके वर्कलोड को ध्यान में रखते हुए उन्हें आराम दिया गया है। राष्ट्रीय चयनकर्ता शॉन फ्लेगलर ने कहा कि भारत के खिलाफ हालिया टी20

सीरीज में मोलिन्यूक्स ने शानदार कप्तानी की थी और यह दौरा उनके नेतृत्व को और मजबूती देगा। उन्होंने बताया कि मोलिन्यूक्स पीठ की चोट से उबर रही हैं और उनके खेलने की संभावना है, हालांकि मैचों के दौरान उनकी फिटनेस का आकलन किया जाता रहेगा। ऑस्ट्रेलिया का यह दौरा 19 मार्च से 2 अप्रैल तक खेला जाएगा, जिसमें तीन टी20 और तीन वनडे मैच खेले जाएंगे। मुकाबले सेंट विंसेंट और सेंट किट्स में होंगे।

ऑस्ट्रेलिया महिला टीम

डार्सी ब्राउन, निकोला कैरी, एश्ले गार्डनर, किम गार्थ, लूसी हैमिल्टन, अलाना किंग, फोएबे लिचफील्ड, ताहलिया मैक्ग्रा, सोफी मोलिन्यूक्स (कप्तान), बेथ मूनी, एलिस पेरी, मेगन शुट, जॉर्जिया वोल, जॉर्जिया वेयरहैम, ताहलिया विल्सन।

वनडे सीरीज आईसीसी महिला चैंपियनशिप का हिस्सा होगी। चयनकर्ताओं के अनुसार यह सीरीज आगामी महिला टी20 विश्व कप से पहले टीम के लिए अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने का अच्छा मौका होगी।

एलपीजी उत्पादन, सीएनजी, पाइप वाली रसोई गैस को आवंटन में मिली शीर्ष प्राथमिकता नया शासनादेश जारी

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण आयातित गैस आपूर्ति बाधित होने के बीच केंद्र सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित प्राकृतिक गैस के आवंटन की प्राथमिकता सूची संशोधित कर दी है। नई व्यवस्था में एलपीजी उत्पादन को सीएनजी और पाइप से मिलने वाली रसोई गैस के साथ शीर्ष प्राथमिकता दी गई है। सरकार की तरफ से जारी गजट अधिसूचना के मुताबिक, इन क्षेत्रों की जरूरतें पहले पूरी की जाएंगी और उसके बाद ही अन्य क्षेत्रों को गैस उपलब्ध कराई जाएगी।

संशोधित व्यवस्था के तहत पाइप के जरिये घरेलू रसोई गैस (पीएनजी), वाहनों के लिए संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) और एलपीजी उत्पादन को प्राथमिकता श्रेणी में सबसे ऊपर रखा गया है। इन क्षेत्रों को पिछले छह महीने की औसत खपत के आधार पर 100 प्रतिशत गैस आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। उर्वरक क्षेत्र को दूसरी प्राथमिकता दी गई है और उसकी पिछले छह महीने की औसत मांग का कम-से-कम 70 प्रतिशत पूरा किया जाएगा। इस सूची में तीसरे

स्थान पर चाय उद्योग, विनिर्माण और अन्य औद्योगिक उपभोक्ताओं को रखा गया है। इन्हें परिचालन उपलब्धता के आधार पर पिछले छह महीने की औसत गैस खपत का लगभग 80 प्रतिशत उपलब्ध कराया जाएगा। शहरी गैस वितरण (सीजीडी) से जुड़ी कंपनियों द्वारा औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को की जाने वाली आपूर्ति को प्राथमिकता सूची में चौथे स्थान पर रखा गया है। भारत में घरेलू गैस उत्पादन लगभग 19.1 करोड़ मानक घन मीटर प्रतिदिन की कुल खपत का करीब आधा हिस्सा ही पूरा कर पाता है। ऐसे में पश्चिम एशिया संकट के कारण गैस आपूर्ति बाधित होने से प्राथमिकता तय करने का फैसला किया गया है। सरकार ने कहा कि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को आपूर्ति बनाए रखने के लिए पेट्रोकेमिकल संयंत्रों, बिजली इकाइयों और ऊंची कीमत पर गैस खरीदने वाले उपभोक्ताओं को मिलने वाली गैस में कटौती की जा सकती है। ईरान पर अमेरिका एवं इजराइल के संयुक्त हमले और फिर ईरान के जवाबी कार्रवाई से पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया है।

इसके कारण होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले समुद्री यातायात में कमी आई है और ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता बढ़ी है। वैश्विक समुद्री तेल व्यापार का लगभग पांचवां हिस्सा और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की लगभग एक-तिहाई आपूर्ति इसी रास्ते से होती है। सरकार ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य के जरिये एलएनजी आपूर्ति बाधित होने के कारण आपूर्तिकर्ताओं ने 'फोर्स मेज्योर' प्रावधान लागू कर दिया है। यह प्रावधान किसी असाधारण या अनियंत्रित परिस्थिति के कारण अनुबंध की शर्तें पूरी न कर पाने पर लागू होता है। ऐसे में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को गैस उपलब्ध कराने के लिए घरेलू गैस आपूर्ति को नए सिरे से व्यवस्थित किया गया है।

अधिसूचना के मुताबिक, पाइपलाइन संचालन के लिए जरूरी कंप्रेसर ईंधन एवं अन्य उत्पादों को भी प्राथमिकता श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि इनके बिना गैस पाइपलाइन का संचालन हो पाना संभव नहीं है। सरकार ने कहा कि इस व्यवस्था का उद्देश्य प्राथमिक क्षेत्रों के लिए गैस आपूर्ति बनाए रखना और उपलब्ध संसाधनों का संतुलित वितरण सुनिश्चित करना है। अधिसूचना के मुताबिक, सरकारी स्वामित्व वाली गैस कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड को प्राथमिकता पर आधारित इस व्यवस्था को लागू करने के लिए प्राकृतिक गैस आपूर्ति प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है।

फरवरी में इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश आठ प्रतिशत बढ़कर 25,978 करोड़ रुपये पर

नई दिल्ली। इक्विटी म्यूचुअल फंड योजनाओं में फरवरी के दौरान शुद्ध निवेश आठ प्रतिशत बढ़कर 25,978 करोड़ रुपये हो गया। उद्योग संगठन एम्फी ने मंगलवार को जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी। इस निवेश के साथ ही म्यूचुअल फंड उद्योग की कुल प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियां (एयूएम) फरवरी महीने में बढ़कर 82 लाख करोड़ रुपये हो गईं। जनवरी में इसका एयूएम 81 लाख करोड़ रुपये था।

'एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया' (एम्फी) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी वेंकट एन चलसानी ने कहा कि इक्विटी योजनाओं में सकारात्मक प्रवाह भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर सहमति बनने के कारण बढ़े निवेशक भरोसे का नतीजा हो सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका, इजराइल और ईरान से जुड़े पश्चिम एशिया के बढ़ते

संघर्ष के कारण इस महीने म्यूचुअल फंड बाजार में कुछ अस्थिरता देखी जा सकती है, लेकिन भारत की दीर्घकालिक वृद्धि की कहानी मजबूत बनी रहेगी। आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी में इक्विटी योजनाओं में 24,028 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश हुआ था, जो फरवरी में बढ़कर 25,978 करोड़ रुपये हो गया। इक्विटी श्रेणी में फ्लेक्सी कैप फंड में सबसे अधिक 6,924.65 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश आया। इसके बाद मिडकैप फंड में 4,003 करोड़ रुपये और स्मॉलकैप फंड में 3,881 करोड़ रुपये का निवेश हुआ। क्षेत्रीय एवं विषयगत फंड में 2,987 करोड़ रुपये और लार्जकैप फंड में 2,112 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश दर्ज किया गया। हालांकि कर-बचत वाली ईएलएसएस योजनाओं से 650 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी हुई। कुल मिलाकर, म्यूचुअल फंड उद्योग में फरवरी के दौरान 94,530 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश आया, जो जनवरी में दर्ज 1.56 लाख करोड़ रुपये से कम है।

इस बीच, गोल्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में फरवरी के दौरान 5,255 करोड़ रुपये का निवेश आया, जबकि जनवरी में यह 24,040 करोड़ रुपये और दिसंबर में 11,647 करोड़ रुपये था। ऋण-आधारित डेट म्यूचुअल फंड योजनाओं में भी पिछले महीने 42,106 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश दर्ज किया गया, जो जनवरी के 74,827 करोड़ रुपये से कम है।

पश्चिम एशिया संकट के बीच निर्यातकों को बीमा समर्थन देने पर विचार: गोयल

नई दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि पश्चिम एशिया संकट के बीच निर्यातकों को मदद देने के लिए सरकार बीमा समर्थन की नई योजना लाने की संभावना तलाश रही है। गोयल ने यहां संवाददाताओं से कहा कि इस संबंध में निर्यात ऋण गारंटी देने वाली इकाई ईसीजीसी और अन्य विभागों के साथ परामर्श किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, "हम निर्यातकों की मदद के लिए बीमा समर्थन जैसी कुछ नई योजनाएं विकसित करने पर भी विचार कर रहे हैं... इस बारे में ईसीजीसी और अन्य विभागों से चर्चा की जा रही है।" उन्होंने कहा कि एक अंतर-मंत्रालयी समूह पश्चिम एशिया संकट से जुड़े घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है और निर्यातकों के साथ लगातार संपर्क में है। गोयल ने कहा कि सरकार उन निर्यातकों की मदद के उपाय तलाश रही है जिनका माल भेजा जा चुका है लेकिन मौजूदा

हालात के कारण उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार चौबीसों घंटे हालात पर नजर रखे हुए है। ईरान और अमेरिका-इजराइल के बीच लगातार जारी हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है, जिससे तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका है। यह संकट भारतीय निर्यातकों के लिए इस लिहाज से अहम है कि भारत के लिए पश्चिम एशिया प्रमुख निर्यात बाजारों में से एक है। इससे पहले गोयल ने 'आहार खाद्य एवं आतिथ्य मेला' को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष निर्यातकों में शामिल होने का लक्ष्य रखना चाहिए।

कच्चे तेल की कीमत में 6% से अधिक की गिरावट भारत जैसे तेल आयातकों को मिलेगी राहत

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ युद्ध जल्द खत्म होने की बात कहे जाने के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल (कच्चे तेल) की कीमत में भी जोरदार गिरावट दर्ज की गई। आज क्रूड ऑयल की कीमत में लगभग छह प्रतिशत की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के कारण ब्रेंट क्रूड 93 डॉलर प्रति बैरल और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड 88 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया। इसके पहले सोमवार को कच्चे तेल की कीमत 119 डॉलर के स्तर को भी पार कर गई थी।

हालांकि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध खत्म होने की बात कहे जाने के बाद कल ही ब्रेंट क्रूड गिरकर 98.96 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर बंद हुआ था। इसके बाद आज ब्रेंट क्रूड ने 91.49 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर कारोबार की शुरुआत की। कारोबार शुरू होते ही ब्रेंट क्रूड टूट कर 88.22 प्रति बैरल के स्तर तक आ गया। हालांकि इसके बाद एक बार फिर इसकी कीमत में तेजी का रुख बना। दोपहर 11 बजे तक का कारोबार होने के बाद ब्रेंड क्रूड 6.14 प्रतिशत की गिरावट के साथ 92.91 प्रति

बैरल के स्तर पर कारोबार कर रहा था। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड ने भी सोमवार को 119 डॉलर प्रति बैरल का स्तर पर करने के बाद 94.77 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर कारोबार का अंत किया था। आज इसने भी 87.81 डॉलर प्रति बैरल के स्तर से कारोबार की शुरुआत की। कारोबार शुरू होने के बाद डब्ल्यूटीआई क्रूड लुढ़क कर 84.43 डॉलर प्रति बैरल के स्तर तक आ गया। इसके बाद इसकी चाल में सुधार हुआ। दोपहर 11 बजे तक का कारोबार होने के बाद डब्ल्यूटीआई क्रूड 6.79 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 88.38 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर कारोबार कर रहा था। इसी तरह वायदा बाजार में ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स आज 6.51 डॉलर प्रति बैरल यानी 6.66 प्रतिशत की गिरावट के साथ फिलहाल 92.45 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं डब्ल्यूटीआई क्रूड फ्यूचर्स आज 6.12 डॉलर प्रति बैरल यानी 6.50 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 88.65 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंचा हुआ है।

आपको बता दे की पश्चिम एशिया में जारी सैन्य तनाव की वजह से सोमवार को कच्चे तेल की कीमत जबरदस्त उछाल के साथ 119 डॉलर का स्तर पार कर 120 डॉलर प्रति बैरल के काफी करीब पहुंच गई थी। हालांकि बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी युद्ध के जल्द खत्म होने की बात कह कर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति को लेकर बनी चिंता को काफी हद तक काम कर दिया। इस वजह से कच्चे तेल की कीमत में गिरावट का रुख बनने लगा। बताया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप से ईरान युद्ध को जल्द खत्म करने के संबंध में बातचीत की। कहा जा रहा है कि इस बातचीत में पुतिन ने अपनी ओर से शांति प्रस्ताव भी पेश किया। इस बातचीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया को दिए इंटरव्यू में ईरान युद्ध जल्द खत्म होने के संकेत दिए।

हालांकि ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स (आईआरजीसी) ने ट्रंप की बात को नकारते हुए कहा कि युद्ध का अंत ईरान तय करेगा और अगर अमेरिका और इजरायल के हमले जारी रहे तो पश्चिम एशिया से एक लीटर तेल का भी एक्सपोर्ट नहीं होने दिया जाएगा। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले 24 घंटे के दौरान ईरान युद्ध को लेकर जिस तरह से अलग-अलग बयान आ रहे हैं, उससे आने वाले कुछ दिन तक कच्चे तेल की कीमत में लगातार उतार-चढ़ाव होते रहने की उम्मीद है। इसके बावजूद कच्चे तेल की कीमत में अभी आई गिरावट भारत जैसे कच्चे तेल के आयात पर निर्भर करने वाले देश के लिए काफी राहत वाली बात है।

गुजरात सरकार ने उद्योगों को गैस आपूर्ति में 50% तक कटौती की

अहमदाबाद। पश्चिम एशिया संकट से गैस आपूर्ति को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच गुजरात सरकार ने घरेलू रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उद्योगों को होने वाली गैस आपूर्ति में 50 प्रतिशत तक कटौती कर दी है। गुजरात के ऊर्जा मंत्री ऋषिकेश पटेल ने मंगलवार को विधानसभा सत्र से पहले यहां संवाददाताओं से कहा कि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी घर में रसोई गैस सिलेंडर की कमी न हो। उन्होंने कहा कि गैस की घरेलू खपत को प्राथमिकता देने के लिए कुछ औद्योगिक उपयोगों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। उन्होंने कहा, "उद्योगों को मिलने वाली गैस आपूर्ति में 50 प्रतिशत की कटौती की गई है। उर्वरक और दूध प्रसंस्करण क्षेत्रों के लिए गैस आपूर्ति में लगभग 40 प्रतिशत कटौती की गई है।"

सोहा अली खान

का 'फुल सर्कल मोमेंट': 17 साल बाद फिर से संयुक्त राष्ट्र से जुड़ीं

मुंबई। अभिनेत्री सोहा अली खान एक बार फिर यूनाइटेड नेशन्स पॉपुलेशन फंड (यूएनएफपीए) के साथ एडवोकेट के रूप में जुड़ गई हैं। इस मौके को उन्होंने अपने जीवन का 'फुल सर्कल मोमेंट' बताया है, क्योंकि अपने करियर की शुरुआत में भी वह संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक संस्था के साथ काम कर चुकी थीं। सोहा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अपने इस नए सफर के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के साथ दोबारा काम करने का मौका मिलना बेहद खास अनुभव है। इस पोस्ट में उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दौर को भी साझा किया और बताया कि उनकी पहली सैलरी वाली नौकरी भी संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक संस्था थी। उन्होंने लिखा कि साल 1999 में मुझे अपनी पहली नौकरी संयुक्त राष्ट्र महिला विकास कोष में मिली थी। उस समय मैं नई दिल्ली में काम करती थी। मेरा काम महिलाओं को आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत बनाना और महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को खत्म करने के लिए जागरूकता फैलाना था। सोहा ने पोस्ट में बताया कि अब करीब 27 साल बाद मैं फिर से संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी हूं। इस बार मुझे यूएनएफपीए का एडवोकेट बनाया गया है। इस बार मैं महिलाओं और लड़कियों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर काम करूंगी। इनमें प्रजनन स्वास्थ्य, मासिक धर्म से जुड़ी जागरूकता, लैंगिक समानता और महिलाओं की गरिमा जैसे विषय शामिल हैं। सोहा ने अपने पोस्ट में लिखा कि मेरे लिए संयुक्त राष्ट्र हमेशा सामूहिक प्रयास का प्रतीक रहा है। मेरा मानना है कि यह एक ऐसा मंच है जहां अलग-अलग देश और समुदाय एक साथ मिलकर लोगों के अधिकार और अवसरों की रक्षा के लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा कि मां बनने के बाद मेरे विचार और भी मजबूत हुए हैं। अब मैं पहले से ज्यादा समझती हूं कि महिलाओं और लड़कियों को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और सम्मान मिलना कितना जरूरी है। यही सोच मुझे लगातार ऐसे कामों से जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। अपने पोस्ट के आखिर में सोहा ने लिखा कि कुछ सफर फुल सर्कल मोमेंट होते हैं। यह मेरे लिए ऐसा ही एक पल है। इस बार मेरे पास पहले से ज्यादा अनुभव है। अब मैं इस नई जिम्मेदारी को पूरी लगन के साथ निभाने के लिए तैयार हूं।

अब सिर्फ अभिनय पर रहेगा फोकस : दिव्या अग्रवाल

मुंबई। हाल ही में रियलिटी शो द 50 से बाहर होने के बाद अभिनेत्री दिव्या अग्रवाल ने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि अब वह आगे किस दिशा में काम करना चाहती हैं। एक इंटरव्यू में दिव्या अग्रवाल ने खुलकर कहा कि शो से बाहर आकर उन्हें राहत महसूस हो रही है। उन्होंने बताया कि यह शो काफी हद तक पुरुष प्रधान था और इसमें काफी ज्यादा शारीरिक गतिविधियां शामिल थीं। उनके मुताबिक शो के दौरान हर प्रतिभागी खुद को सामने लाने की कोशिश में लगा रहता था, जिसके कारण कई बार कंटेस्टेंट एक-दूसरे के बारे में अजीब या अनचाही बातें भी कह देते थे। ऐसे हालात कई बार माहौल को असहज बना देते थे। दिव्या ने यह भी बताया कि उन्होंने इस शो में हिस्सा अपने फैंस की वजह से लिया था। लंबे समय से उनके प्रशंसक चाहते थे कि वह किसी और रियलिटी शो में नजर आएं। इसी वजह से उन्होंने द 50 का हिस्सा बनने का फैसला किया। हालांकि अब उनका कहना है कि वह भविष्य में किसी भी तरह का रियलिटी शो करने की योजना नहीं बना रही हैं। दिव्या ने स्पष्ट किया कि आगे उनका पूरा ध्यान केवल अभिनय पर रहेगा और वह अपने एक्टिंग करियर को मजबूत बनाने पर फोकस करना चाहती हैं। अगर उनके करियर की बात करें तो दिव्या अग्रवाल ने मनोरंजन जगत में अपनी पहचान एक रियलिटी शो प्रतिभागी के रूप में बनाई। साल 2017 में उन्होंने एमटीवी स्प्लीटसविला 10 में हिस्सा लिया था, जहां वह अभिनेता प्रियंक शर्मा के साथ रनर-अप रहीं। इसी शो से उन्हें व्यापक पहचान मिली और वह दर्शकों के बीच लोकप्रिय होने लगीं। इसके बाद 2018 में दिव्या ने एमटीवी एसीई आफ स्पेस में भाग लिया और इस शो की विजेता बनीं। इस जीत ने उन्हें टीवी इंडस्ट्री में मजबूत पहचान दिलाई। बाद में उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा और हॉरर वेब सीरीज रागिनी एमएमएसः रिटर्नस के दूसरे सीजन में नजर आईं। उनके करियर का बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने बिग बॉस ओटीटी सीजन 1 का खिताब जीता।

सन्नाटे में अलग तरह की सुंदरता और आश्चर्य छिपा हुआ हैः अमिताभ

मुंबई। हाल ही में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में मुंबई की रातों की अनोखी शांति और उसके भावनात्मक अनुभव को शब्दों में व्यक्त किया है। बिग बी यूं तो अक्सर अपने पिता हरिवंश राय बच्चन की कविताओं से प्रेरित होकर लिखते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपने मन की अनुभूतियों को सीधे तौर पर साझा किया। अमिताभ बच्चन ने बताया कि दिनभर की भागदौड़ और भीड़भाड़ के बाद रात के समय मुंबई जैसे व्यस्त शहर में भी एक अजीब-सी शांति फैल जाती है। सड़कें लगभग खाली हो जाती हैं और चारों ओर गहरा सन्नाटा छा जाता है। उनके अनुसार यह सन्नाटा कई लोगों को डरावना लग सकता है, लेकिन उनके लिए इसमें एक अलग तरह की सुंदरता और आश्चर्य छिपा हुआ है। उन्होंने लिखा कि रात की खामोशी शहर के एक बिल्कुल अलग रूप से परिचित कराती है। अपने ब्लॉग में उन्होंने देर रात का एक छोटा-सा अनुभव भी साझा किया। उन्होंने बताया कि जब वह यह सब लिख रहे थे, तभी अचानक एक कार सड़क के गड्ढे से टकराई और कुछ पल के लिए सन्नाटा टूट गया। रात करीब एक बजे कभी-कभी किसी तेज रफ्तार बाइक के एग्जॉस्ट की आवाज भी सुनाई दे जाती है। उनके अनुसार शायद कोई व्यक्ति देर रात काम से लौट रहा होता है या फिर नई शिफ्ट के लिए निकल रहा होता है। ऐसी छोटी-छोटी आवाजें रात की खामोशी को और गहरा बना देती हैं। अपने विचारों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने प्रकृति को सबसे बड़ी औषधि बताया। उनके अनुसार जीवन में शोर और सन्नाटा, व्यवस्था और अव्यवस्था, सब साथ-साथ चलते रहते हैं। अमिताभ ने मुंबई के आसमान की बदलती खूबसूरती का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि इन दिनों शहर का आसमान पहले से ज्यादा साफ और नीला दिखाई दे रहा है। निर्माण कार्यों के दौरान पानी के छिड़काव से धूल नीचे बैठ जाती है, जिससे हवा अपेक्षाकृत स्वच्छ हो जाती है। इसके अलावा बारिश के दिनों में भी प्रदूषण कम हो जाता है, क्योंकि बारिश धूल और मिट्टी को धोकर साफ कर देती है। समुद्र किनारे बसे होने के कारण समुद्री हवाएं भी वातावरण को ताजा बनाए रखने में मदद करती हैं।